fo"k; lwph

lEikndh;

कमल संदेश

आतंकवाद

आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई.... 5

विशेष लेख

गिरता शेयर बाजार
शरद जैन........................ 13

असम में बहुसंख्यकों की सुरक्षा
विमलांगशु राय................ 24

साक्षात्कार

प्रो. प्रेम कुमार धूमल.............. 16

अन्य

भाजपा ने लम्बी छलांग लगायी.10

सत्यम प्रकरण......................... 12

'शिबू सोरेन' उपचुनाव हारे..... 15

विजय संकल्प रैली : शिमला.. 18

प्रदेश कार्यसमिति बैठक

उत्तराखंड................................ 19

मध्य प्रदेश.............................. 21

उत्तर प्रदेश............................. 23

राज्यों से

असम (11), जम्मू–कश्मीर(14)
कर्नाटक(14), उ.प्र.(15/29),
म.प्र.(22), दिल्ली,(30), गुजरात(30)

सम्पादक

çHkkr >k] lkln

सम्पादक मंडल

lR;iky

d- d- 'kek

lthO dekj flUgk

jkeu;u flg

पृष्ठ संयोजन

/keZUæ dk'ky

सम्पर्क

Mk- eqdthZ Lefr U;kl
ihih&66] lqcze.;e Hkkjrh ekxZ
ubZ fnYyh&110003
Qku u- +91¼11½&23381428
QDl % +91¼11½&23387887

सदस्यता शुल्क

okf"kZd 100#- | f=okf"kZd 250#-

e-mail address

kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

{ संतोष नन्दन वन के समान है। मनुष्य अगर अपने अन्दर उसे स्थापित करे तो उसे वैसे ही सुख मिलेगा जैसे नन्दन वन में मिलता है। }

-चाणक्य

राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा जरूरी

''चिदम्बरम सबूत लेकर अमेरिका जाएंगे'' न इसमें रौब है, न इसमें साख है और न इसमें धाक है।'' यूपीए सरकार का यह गिड़गिड़ाना हर स्वाभिमानी भारत को चोट पहुंचा रहा है। अटलजी ने कहा था भारत–पाक के मसले पर किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। पर समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कौन सी मजबूरी है जो वे पाकिस्तान के विरूद्ध उपलब्ध सबूत को अमेरिका तक ले जाने की उत्सुकता दिखा रहे हैं। क्या यूपीए सरकार यह समझ रही है कि पाकिस्तान के विरूद्ध उसके पास कोई सबूत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम स्वयं दिग्भ्रमित हो रहे हैं या पाक को मूर्ख बना रहे हैं या अमेरिका के सामने हम घुटने टेक रहे हैं।

'युद्ध गुड्ड़े–गुड़ियों का खेल नहीं है। यह राजनीतिक शह और मात नहीं है। यह चौसर की चोंचलेबाजी भी नहीं है। युद्ध राष्ट्र की अस्मिता से जुड़ा होता है। युद्ध व्यक्ति नहीं राष्ट्र लड़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेसनीत यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और विदेशमंत्री जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं इसे घुड़की देना ही कहेंगे। भारत जैसे राष्ट्र को घुड़की देने की भाषा शोभा नहीं देता। आसिफ अली जरदारी कुछ भी बोले तो लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते हैं पर भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो लोग उसे गंभीरता से लेते हैं। वर्तमान यूपीए सरकार ने इस गंभीरता को बुरी तरह से आहत किया है।

यूपीए सरकार को यदि जनमानस की भद करनी थी तो जिस दिन मुंबई के ताज होटल नहीं भारत मां के ताज पर हमला हुआ था उसी दिन ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए था। काश ऐसा होता तो लोग मनमोहन सिंह को इतिहास के पन्ने में अंकित कर देते। हमें स्मरण रखना होगा कि कारगिल के युद्ध को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटलजी ने इतिहास के सुनहरे पन्ने पर अमर कर दिया था। आज जिस भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री सहित उनके मंत्री कर रहे हैं वह युद्ध की बानगी के बजाय राजनीति की बू से भरी है। नाभिकीय करार में अमेरिका की भूमिका को देखने के बाद भी अमेरिका पर विश्वास करने को वर्तमान सरकार की नादानी कही जाय या नासमझी, समझ में नहीं आता।

अभी तक यूपीए को यह नहीं समझ नहीं आ रहा कि पाक अमेरिका की भाषा बोल रहा है। कोंडालिजा राइस जिस दिन भारत में आती हैं नई दिल्ली की भाषा और पाक में कराची की भाषा बोलती हैं। अमेरिका की चालाकी को समझने की क्षमता खो चुकी यूपीए सरकार पूरी तरह से विदेश नीति के मसले पर असफल रही हैं। विश्व भर के देश भारतीय कूटनीति का लोहा मानते रहे हैं। इस कड़ी में देखें तो अटलजी सर्वाधिक सफल रहे। हम सबको याद रखना होगा कि कारगिल युद्ध के दौरान अमेरिका ने नवाज शरीफ और अटलजी को वाशिंगटन बुलाया था। नवाज शरीफ दौड़े–दौड़े गए थे और अटलजी ने कहा था कि अभी

हमें अमेरिका की कोई आवश्यकता नहीं है और वे वतन में बने रहे। अटलजी के कार्यकाल में जब परमाणु विस्फोट हुआ तो 45 देशों ने प्रतिबंध लगाया था यहां तक कि वे पांच राष्ट्र भी, जो अपने को परमाणु शक्ति संपन्न मानते है, ने हम पर प्रतिबंध लगाया था पर अटलजी ने इन सभी राष्ट्रों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का डटकर मुकाबला किया और भारत को खड़ा कर दिया।

भारत आज किसी राष्ट्र का मोहताज नहीं है। जो लोग भारत को पाक की निगाह से देखते हैं उन्हें शायद भारत के सामर्थ्य का पता नहीं है। युद्ध किसी भी वार्ता के असफल होने की अंतिम परणति है। वार्ता का प्रारंभ युद्ध से नहीं होता। बात रही वार्ता की तो पाक वार्ता लायक बचा नहीं। जब तक दो टूक निर्णय पर राष्ट्र को नहीं ले जाएंगे तब तक पाक के हौसले पस्त नहीं होंगे। हमें युद्ध के पूर्व की क्रिया प्रारंभ करनी होगी। पहले देश को एकजुट करना होगा। राष्ट्र सबका है न कि कांग्रेसनीत यूपीए का। युद्ध देश लड़ता है दल नहीं। अतः अनिवार्यता यह है कि पहले सरकार हर भारतीय का समर्थन प्राप्त करे। जनमत का निर्माण करे और जनमत को समझे। क्या पाक अधिकृत कश्मीर में आईएसआई के जो आतंकी प्रशिक्षण शिविर है उनको समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या उन बंकरों को समाप्त नहीं किया जा सकता जिनके गर्भ में आतंकी पलते हैं। दिक्कत तो यह है कि सर्वोच्च न्यायालय से फांसी की सजा प्राप्त अफजल को मौत देने के बजाय उसे भारतीय जेल में सरकारी धन पर पाला जाता है। इंतिहा हो गई तुष्टिकरण की। हम तुष्टिकरण की आड़ में और क्या–क्या करना चाहते हैं? वोट से बड़ा देश है। लोग कांग्रेसनीत यूपीए पर आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि वो चुनावी जंग जीतने के लिए भारत को जंग में झोंकना चाहते हैं। भगवान करे यह आशंका गलत हो पर यदि ऐसा है तो देशवासियों को सचेत होना पड़ेगा। चुनाव जीतने के लिए नहीं युद्ध तो भारत की अस्मिता बचाने के लिए होना चाहिए। कांग्रेसनीत यूपीए सरकार को इसका जवाब देना होगा। ■

जन्मदिन पर अटलजी को मिली बधाइयां

भाजपा के शीर्षस्थ नेता व पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस (25 दिसंबर) पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल व उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने गुलदस्ते भेजकर उन्हें शुभकामनाएं दीं, जबकि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लोकसभा में विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी व भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने श्री वाजपेयी के आवास पर पहुंच कर उन्हें 85वें जन्मदिन की बधाई दी। प्रधानमंत्री लगभग 15 मिनट तक श्री वाजपेयी के साथ भी रहे। मुंबई पर आतंकी हमले में पीड़ितों के दुख दर्द में शामिल होते हुए श्री वाजपेयी ने जन्मदिन के मौके पर अपने आवास पर कोई कार्यक्रम नहीं रखा था। हालांकि उन्होंने बधाई देने आए प्रमुख लोगों से मुलाकात की और शुभकामनाएं स्वीकार की। श्री वाजपेयी को बधाई देने गए अन्य प्रमुख नेताओं में राज्यसभा में विपक्ष के नेता जसवंत सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भुवनचंद्र खंडूड़ी, इनेलो के नेता ओम प्रकाश चौटाला समेत भाजपा संगठन के तमाम पदाधिकारी व अन्य नेता शामिल थे। बाद में शाम को श्री वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी ने श्री वाजपेयी के साथ फिल्म देखने के यादगार लम्हों समेत पिछले पचास सालों के साथ को याद किया। उन्होंने राजग सरकार के समय दैनिक जागरण में श्री वाजपेयी व श्री शेखावत के साथ प्रकाशित फोटो का जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह हम तीनों नेताओं ने दशकों तक एक साथ काम किया। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत ने वाजपेयी के साथ सहयोग का जिक्र करते हुए राजनीति में स्वच्छ लोगों के आने की जरूरत पर बल दिया। भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह, जद(यू) के अध्यक्ष शरद यादव व इनेलो के प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने भी श्री वाजपेयी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। शरद यादव ने तो 1974 के अपने पहले चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी जीत में वाजपेयीजी की दो सभाओं का बड़ा योगदान रहा। ■

निर्णायक लड़ाई तक लड़ना होगा : राजनाथ सिंह

ik किस्तानी आतंकवादियों द्वारा मुंबई में किए गए भारी आतंकी हमले को हुए एक मास से अधिक समय बीत चुका है। 26 नवम्बर को हुआ यह आतंकी हमला न केवल मुंबई के लोगों के प्रति आक्रमण की कार्रवाई थी, बल्कि भारत की संप्रभुता और प्रतिष्ठा पर किया गया एक क्रूर हमला था। तभी से वर्तमान सरकार की तरफ से तरह–तरह का शोर–शराबा सुनाई पड़ रहा है। किन्तु, देश के लोगों को मुंबई पर आतंकी हमला करने वाले अपराधियों के विरूद्ध सरकार द्वारा किसी ठोस कार्रवाई किए जाने का अभी भी इंतजार है।

यद्यपि भारत ने मुंबई हमले से पाकिस्तान का निकटतम संबंध होने का अकाट्य साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है तब भी पाकिस्तानी राज–प्रतिष्ठान इससे खुले रूप में इंकार कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने मुंबई पर हमला करने वालों को दबोचने में भारत के साथ सहयोग करने से मना कर दिया है तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस निर्देश की भी अवहेलना की है, जो सुरक्षा परिषद ने "जमात–उद–दावा" जैसे आतंकवादी संगठनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के बारे में दिया था।

पाकिस्तान भाड़े के जेहादियों की शरणस्थली और वैश्विक आतंकवाद की जन्मभूमि बनकर उभरा है। पाकिस्तान से यह अपेक्षा करना एक नौसिखियापन होगा कि वह अपनी भूमि से आतंकवाद चला रहे आतंकवादियों के विरूद्ध कोई सख्त कार्रवाई करे। अतः इसकी पूरी जिम्मेवारी हमारे कंधों पर आ गई है कि हम आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई को अंतिम मुकाम तक ले जाएं।

संप्रग सरकार राष्ट्र के मुद्दों को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय – विशेषतया अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर हो रही है। जब तक भारत स्वयं दृढ़ इच्छा तथा संकल्प के साथ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए स्वयं पहल नहीं करता है तब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा 29 दिसम्बर, 2008 को मुंबई में जारी प्रेस वक्तव्य

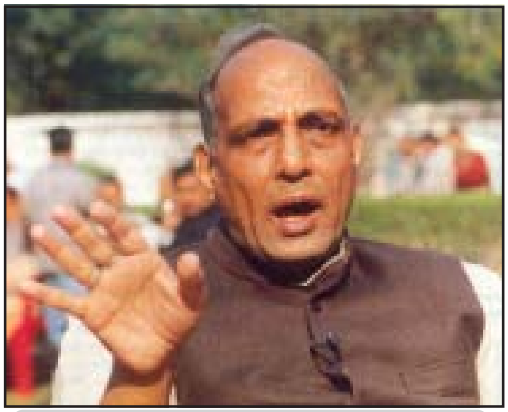

सबसे पहले संप्रग सरकार को अमेरिका जैसे देशों से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता की प्राप्ति के स्रोतों को बंद करने के लिए राजनयिक विकल्पों का सहारा लेना चाहिए।

सहानुभूति के कुछ शब्द कहने से अधिक कुछ नहीं करेगा।

एक प्रभुतासंपन्न राष्ट्र होने के नाते भारत को अपनी सुरक्षा, प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा करने के लिए विश्व के किसी भी देश से मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार को उन लोगों को समझाने के लिए सबूत इकट्ठा करने के अलावा और अधिक कार्रवाई करने की जरूरत है, जो अपना संकीर्ण, सामरिक हित साधने में लगे हुए हैं।

सबसे पहले संप्रग सरकार को अमेरिका जैसे देशों से पाकिस्तान को वित्तीय सहायता की प्राप्ति के स्रोतों को बंद करने के लिए राजनयिक विकल्पों का सहारा लेना चाहिए।

अमेरिका से पाकिस्तान को प्रतिवर्ष लगभग 2 बिलियन डॉलर की सहायता मिलती है। हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए 7.6 बिलियन डॉलर का सहायता पैकेज दिलवाने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक उपकरण के रूप में भूमिका निभाई थी।

अमेरिका के दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित विश्वसनीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान पश्चिमी देशों से मिलने वाली वित्तीय सहायता को बदल कर आतंकी मॉड्यूल्स को तथा भारत के शहरों पर आतंकी हमलों को पोषित करने पर खर्च कर रहा है।

अमेरिका के मनोनीत राष्ट्रपति मिस्टर बराक ओबामा ने अपने चुनावी अभियान के दौरान स्वयं भी पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी सहायता को भारत के विरूद्ध दुष्प्रयोग किए जाने पर चिंता व्यक्त की थी। जब तक पाकिस्तान विदेशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करता रहेगा तब तक ही वह आईएसआई के माध्यम से उस धन को बदलकर भारत को अस्थिर बनाने और हानि पहुंचाने पर खर्च करता रहेगा।

भारत के साथ परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद ऐसा माना गया था कि अमेरिका भारत का सामरिक सहयोगी हो गया है। संप्रग सरकार ने स्वयं भी अनेक मंचों से इस तथ्य का खुलासा किया था। अब वक्त आ गया है कि भारत सरकार राजनयिक चैनलों का उपयोग करते हुए अमेरिका से पाकिस्तान को मिलने वाली सारी वित्तीय सहायता बंद कराए और साथ मिलकर पाकिस्तान पर आर्थिक प्रतिबंध लगवाने

ओमप्रकाश कोहली दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष घोषित

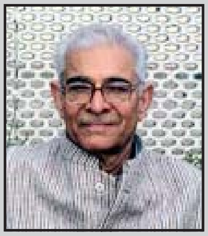

Jh vkeidk'k dkgyh dk nljh ckj Hkktik fnYyh çns'k vè;{k dk nkf;Ro lkik x;k gA Jh dkgyh 1993 l 1996 rd fnYyh Hkktik d vè;{k jg pqd gA

f'k{kd urk vkj iol e fo|kFkh ifj"kn l tqM Jh dkgyh rhu ckj fo|kFkh ifj"kn d vf[ky Hkkjrh; vè;{k jg] nk ckj fnYyh fo'ofo|ky; f'k{kd l?k d vè;{k jgA o"k 1992 e Jh dkgyh fnYyh ins'k d Hkktik vè;{k cuA bud urRo e fnYyh e igyk foèkkulHkk pquko gvkA ftle ikVh dk nk frgkbl cgqer feykA Jh dkgyh jkT;lHkk lkln rFkk fnYyh ;equkikj fodkl ckMl d vè;{k Hkh jg pqd gA ■

की कार्रवाई करे।

ऐसा घातक हमला सहने के पश्चात् भारत सरकार के लिए कुछ सरकारी प्रतिनिधियों/अधिकारियों तथा भारतीय क्रिकेट टीम के पाकिस्तान के दौरे को रद्द किया जाना ही काफी नहीं है। भारत के विरूद्ध ऐसे घृणित अपराध को अंजाम देने वाले अपराधियों को भारत को सौंपने से दो टूक इनकार के विरोध में भारत को तत्काल भारत–पाक के आतंकवाद–विरोधी संयुक्त तंत्र से हट जाना चाहिए तथा पाकिस्तान के साथ अपने आर्थिक और वाणिज्यिक रिश्ते समाप्त कर लेने चाहिए।

भविष्य में 11/26 जैसे हादसे की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भारत के लिए यह जरूरी हो गया है कि वह उन लोगों की सफलतापूर्वक पहचान करे, जिन्होंने उक्त आतंकी हमलों की योजना बनाई थी और सरकार उन हमलों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए लश्कर, जमात–उद–दावा तथा आईएसआई जैसे संगठनों के विरूद्ध अभियोग चलाए। इन लोगों और संगठनों पर हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में युद्ध–अपराधों के लिए मुकद्मा चलाया जाना चाहिए क्योंकि मुंबई पर हुआ हमला भारत के विरूद्ध खुली जंग थी।

सैनिक हमले अंतिम विकल्प हो सकते हैं किंतु उनसे पहले सरकार को अन्य विकल्पों का भी सहारा लेना चाहिए। ये ऐसे विकल्प हैं, जिन पर सार्वजनिक तौर पर चर्चा नहीं की जाती है, बल्कि जिन्हें गुप्त रूप से अंजाम दिया जाता है। सक्रिय प्रतिविरोधपरक नीति न केवल सरकार के इरादे का संकेत देगी, बल्कि कुछ करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर दबाव डालने में देश की मदद करेगी।

भारत सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को विश्वास में लेना चाहिए तथा उन्हें पाकिस्तान से की जा रही आंतकी कार्रवाइयों के विरूद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की देख रेख के अधीन मिली जुली सैनिक कार्रवाई करने हेतु मनाना चाहिए।

समाचार पत्रों की रिपार्टों से संकेत मिला है कि पाकिस्तानी नौसेना पहले ही युद्ध के लिए उद्यत हो चुकी है। भारत को कराची की नौ सेना घेराबंदी के विकल्प पर विचार करना चाहिए जोकि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार किया जाने वाला उपाय है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार न केवल मतिभ्रम की शिकार है बल्कि आंतकवाद के विरूद्ध सौदेबाजी करने और राष्ट्रीय ऐजेन्डे में पलीता लगाने के लिए भी इच्छुक है।

हाल ही मे सरकार में इस बात पर भी गहरे मतभेद पैदा हो गए हैं कि आतंकवाद से लड़ने के लिए क्या कार्यविधि अपनाई जाए। एक ओर विदेश मंत्री कह रहे हैं, ''सभी विकल्प खुले हैं।'' दूसरी ओर प्रधानमंत्री का बयान आया है कि ''युद्ध कोई विकल्प नहीं है।''

जिस त्रासदी ने लगभग 200 बेगुनाह सिविलियनों तथा सुरक्षाकर्मियों की जीवनलीलाएं समाप्त हुईं उसका तकाजा है कि आतंकवाद के विरूद्ध लगातार कठोर कार्रवाई की जाए। आतंकवाद के ढांचे को ध्वस्त करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है तथा इस कर्त्तव्य को अंजाम देने के लिए भारत को कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए।

भारतीय जनता पार्टी ने उन तत्वों के विरूद्ध भारत सरकार द्वारा की जाने वाली किसी भी ठोस कार्रवाई को अपना पूर्ण हार्दिक समर्थन देने का वादा किया है जो मुम्बई पर हुए हमले से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं किन्तु सरकार को चाहिए कि वह अपनी कथनी के अनुसार ठोस कार्रवाई करे।

जम्मू-कश्मीर में भाजपा का उत्साहजनक प्रदर्शन

जम्मू–कश्मीर विधानसभा के चुनाव परिणामों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि भाजपा अपना प्रभाव चतुर्दिक फैला रही है। इतिहास की पुस्तकों में वर्ष 2008 भाजपा के लिए उल्लेखनीय वर्ष माना जाएगा जिसके दौरान पार्टी ने न केवल अपना जनाधार मजबूत किया है बल्कि दक्षिण में कर्नाटक जैसे राज्य और उत्तर में जम्मू–कश्मीर जैसे राज्य तक में अपना प्रभाव बढ़ाया है। अब हम जम्मू–कश्मीर में एक बड़ी शक्ति के रूप में बनकर उभरे हैं जहाँ हमारे विधायकों की संख्या 1 से बढ़ कर 11 हो गई है।

पार्टी का जम्मू–कश्मीर में उत्साहवर्धक प्रर्दशन पूरी भाजपा के लिए एक संजीवनी है जो अगले वर्ष होने वाले आम चुनावों के लिए सघन तैयारी में जुटी हुई है। भाजपा का राष्ट्रवादी ऐजेन्डा और विकास के प्रति उसकी अचल प्रतिबद्वता को भारत के लोगों द्वारा व्यापक रूप से सराहा गया है। भाजपा इसी पथ का अनुसरण करती रहेगी।

भाजपा तथा राजग में इसके सहयोगी दल सुनिश्चित करेंगे कि आम चुनाव 2009 में विजय प्राप्त करने के पश्चात केन्द्र में श्री लालकृष्ण आडवाणी नीत सरकार सत्ता ग्रहण करेगी जो भारत के लिए अनेक सम्भावनाओं के द्वार खोलेगी।■

पाक के खिलाफ सिर्फ गरजने से काम नहीं चलेगा : डा. मुरली मनोहर जोशी

Hkk जपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ गरजने की नीति पर काम कर रही है लेकिन सिर्फ गरजने से काम नहीं चलेगा। श्री जोशी ने 26 दिसम्बर को एक संवाददाता सम्मेलन में आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान से निपटने के तौर तरीकों पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि हमारे विदेश मंत्री सिर्फ गरज रहे हैं। सिर्फ गरजते रहना देश को तो धोखे में डालता है और जेहादियों को तैयारी का मौका मुहैया कराता है। उन्होंने आह्वान किया कि अब समय आ गया है जब देश में हर स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी होनी चाहिए।

श्री जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार को विपक्ष और देश की जनता को विश्वास में लेना चाहिए कि आखिर उसने मुंबई बम धमाकों के मामले में पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करने का मन बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार इस बारे में जनता या विपक्ष को कुछ नहीं बताना चाहती और देश की तैयारियों के राज को सामने नहीं लाना चाहती तो कोई बात नहीं। लेकिन इस बारे में कुछ बोलने में उसे क्या झिझक है यह तो उसे जरूर साफ कर देना चाहिए।

पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार के कोरे शब्द बाणों से जेहादी सतर्क हो गए हैं और यहां तक कह दिया है कि वे परमाणु शक्ति से संपन्न इकलौते इस्लामिक देश पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर तहस नहस नहीं होने देंगे। श्री जोशी ने कहा कि पाकिस्तान की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वह भारत पर ही आरोप लगाने लगा है कि उसके पास पाकिस्तानी आतंकवादियों के मुंबई हमले में शामिल होने के कोई सबूत नहीं हैं। उल्टे उसने दावा किया है कि पाकिस्तान के पास भारत के खिलाफ वहां के आतंकी हमलों में शामिल होने के सबूत हैं। यहां तक कि उसने जमात उद दावा पर पाबंदी लगाने के संयुक्त राष्ट्र संघ के फैसले का भी मखौल बना दिया है। पाकिस्तान में बैठे जेहादी और आतंकवादी संगठन भारत को बर्बाद करने की धमकी दे रहे हैं लेकिन सरकार अब तक नहीं चेती है।

श्री जोशी ने कहा कि देश से आतंकवाद को खत्म करने के लिए यदि केंद्र सरकार अगर कोई कड़े कदम उठाती है तो भाजपा उसकी हर तरह से मदद करेगी। उन्होंने कहा, 'शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र रक्षा प्रवर्तते' अर्थात जब राष्ट्र की ताकत या हथियारों के साथ रक्षा की जाती है तो वहां विद्या और ज्ञान की भी रक्षा होती है। जोशी ने मुंबई आतंकवादी हमले के संबंध में बेतुका बयान देने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री एआर अंतुले को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की।

उन्होंने कहा कि अंतुले के बयान पर केंद्र सरकार की सफाई पूरी तरह हास्यास्पद है। एक तरह से अंतुले ने अपने बयान को वापस लेने से इंकार कर दिया और सरकार के अन्य मंत्रियों को उनकी सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक के लिए अंतुले को बचा रही है। ■

पाक को मुंबई हमलों का जवाब उसकी भाषा में ही दे भारत : नरेन्द्र मोदी

गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का कहना है कि पाकिस्तान को मुंबई हमलों का जवाब उसकी ही भाषा में देना चाहिए। श्री मोदी ने संसद में हाल ही में पारित आतंकवाद निरोधक कानूनों के बारे में चर्चा की। उन्हें लगता है कि 19वीं सदी के कानूनों के जरिए आतंकवाद से नहीं निपटा जा सकता। श्री मोदी इस बात से सहमत नहीं हैं कि राजस्थान और दिल्ली में हुए विधानसभा चुनावों में आतंकवाद का मुद्दा भाजपा के लिए कारगर नहीं रहा। मुंबई हमलों की पृष्ठभूमि में उन्होंने इन राज्यों में चुनाव प्रचार किया था। ऐसा उन गिने चुने लोगों का कहना है जो पाकिस्तान और कांग्रेस की मदद करना चाहते हैं।

गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि चार राज्यों दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा ने कुल 294 सीटें और कांग्रेस ने 274 सीटें जीतीं। इससे पता चलता है कि आतंकवाद के खात्मे के लिए जनता ने भाजपा का समर्थन किया है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमलों को 'देश पर हमलों बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि जनता चाहती है कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार ने मुंबई हमलों के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) गठित करने और गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक अधिनियम में संशोधन करने जैसे कदम उठाए हैं। श्री मोदी के मुताबिक ये सिर्फ छलावा हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए कानूनी सहारा देने में ये कदम नाकाफी हैं। इनका मकसद यह बताना है कि उन लोगों की राय बदल गई है जो कहते हैं कि कानूनों से आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते।

श्री मोदी ने कहा—मुंबई हमले भारत पर पाकिस्तान का हमला ही तो थे। अब भारत को जवाब देना है। केन्द्र सरकार को तय करना है कि जवाब देने का सही तरीका क्या हो। आम जनता की तो यह इच्छा है कि भारत पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे। अमेरिका की तरह ही केन्द्र सरकार को और हर राज्य को पूरी असहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए। कांग्रेस नीत यूपीए सरकार आतंकवाद के मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। गठबंधन को तय करना होगा कि वह ऐसी नीतियों को जारी रखेगा या आम जनता की ओर ध्यान देगा। वे वोट बैंक की जितनी राजनीति करेंगे आम आदमी उतना अधिक असुरक्षित होता जाएगा। अफजल गुरू को फांसी न देकर और आतंकवाद निरोधक कानून पोटा को खत्म कर उन्होंने आतंकवाद को बढ़ावा ही दिया है। ■

वैश्विक आतंकवाद का केन्द्र है पाकिस्तान : रविशंकर प्रसाद

अब वक्त आ गया है कि भारत पाकिस्तान से आए उन आतंकियों को "Non State Actors" ("राज्य विहीन" अपराधी) कहना बंद कर दे, जिन्होंने मुंबई में जघन्यतम आतंकी हमला किया था। पाकिस्तान ने अपना दामन बचाने के लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया था। यह शब्दावली पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र से भारत पहुंचे आतंकवादियों के बारे में बार–बार इंकार करते समय प्रयोग की थी। इसीलिए राज्यविहीन अपराधियों को बाद में पाकिस्तान द्वारा "फ्रीलांसर" के नाम से पुकारा जाने लगा।

इसके विपरीत, इस बात के ठोस साक्ष्य उपलब्ध हैं कि इन आतंकवादियों को हथियारों और प्रशिक्षण की वे सभी सुविधाएं जुटाई गई थीं, जो पाकिस्तान की प्रमुख संस्थाओं की सक्रिय संलिप्तता के बिना उनको मिलनी असंभव थीं। जिन हथियारों, ग्रेनेडों तथा विस्फोटकों का उन्होंने प्रयोग किया था, उन पर वही चिह्न अंकित थे, जो पाकिस्तानी सेना द्वारा प्रयुक्त हथियारों पर अंकित रहते हैं। आतंकवादियों द्वारा प्रयोग में लाई गई उन्नत किस्म की जीपीएस प्रणाली (GPS System) और कराची से मुंबई तक किए गए मेरीटाइम आपरेशन्स स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि आतंकवादियों को मेरीटाइम और शहरी युद्ध कला में विशेष प्रशिक्षण दिया गया था जो केवल वहीं संभव हो सकता है, जहां नौसेना के कमांडोज को प्रशिक्षित किया जाता है। वस्तुतः, ऐसी रिपोर्ट मिली हैं कि उन्हें नौसेना कमांडोज को सुलभ पीएनएस इक्बाल (PNS Iqbal) में विशिष्ट प्रशिक्षण दिया गया था।

अतः यह पूरी तरह स्पष्ट है कि आईएसआई के प्रमुख तत्वों द्वारा इस प्रकार के आतंकी हमले की पूरी योजना तैयार की गई थी। अतः यह भारत के लिए बहुत लाजिमी हो जाता है कि वह आगे 'राज्यविहीन अपराधी' शब्दावली का प्रयोग करना बंद कर दे। वे पाकिस्तानी आतंकवादी थे और पाकिस्तान के सरकारी इजारों के कर्मियों ने इस आतंकी हमले में उनकी भरपूर मदद की थी। भारत को आईएसआई के विरूद्ध अग्र मोर्चा खोलना चाहिए और उसको एक आतंकी संगठन घोषित किए जाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। दाउद इब्राहीम के जन्मदिन पर कल इस्लामाबाद में हुए समारोह में आईएसआई अधिकारियों की कथित संलिप्तता इसका अगला ठोस प्रमाण है। यह भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दा नहीं है, जैसाकि कुछ एक देशों द्वारा इसे इस प्रकार का रूप देने का प्रयास किया जा रहा है बल्कि, मुख्य मुद्दा यह है कि पाकिस्तान वैश्विक आतंकवाद का केन्द्र बनकर उभरा है। अतः यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है, कि आगे और अधिक कड़े राजनयिक उपाय किए जाएं क्योंकि पाकिस्तान हमलों में अपनी लिप्तता से और आतंकवाद को समाप्त करने की कार्रवाई करने से लगातार इंकार कर रहा है। किसी घोर आपात स्थिति को छोड़कर, दोनों देशों के बीच आवागमन पूरी तरह बंद कर दिया जाना चाहिए। सरकार को पाकिस्तान स्थित अपने उच्चायोग के कार्यकलाप को कम करने और अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने के बारे में भी विचार करना चाहिए। यह शोर–शराबा किए बिना कार्रवाई करने का समय है तथा सरकार को एक स्वर में ही अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।■

पाक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई से पीछे हट रहा है केन्द्र : भाजपा

भारतीय जनता पार्टी ने केन्द्र की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के सवाल पर पांव पीछे खींचने का आरोप लगाया है। पार्टी ने सरकार से पूछा है कि क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत अगले हमले का इंतजार करेगा।

भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावडेकर ने कहा कि पार्टी को गृहमंत्री पी चिदम्बरम के उस बयान से काफी निराश हुई है जिसमें उनका कहना था कि अगर पाकिस्तान फिर हमला करेगा तो उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने पूछा, 26/11 के हमले की पाकिस्तान क्या कीमत चुकाएगा। क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत हमले का इंतजार करेगा।'' उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की थी जो अब भारी कीमत चुकाने के बयान पर आकर थम गई है। सरकार अपना कदम पीछे खींच रही है।

भाजपा प्रवक्ता का कहना था कि पार्टी तो शुरू से ही कह रही है कि पाकिस्तान के प्रति यूपीए सरकार का रवैया काफी नरम रहा है।

श्री जावडेकर ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पाकिस्तान के विरूद्ध संप्रग सरकार की बार–बार चेतावनियां मुंबई में हुए 26/11 के हमले में उसकी संलिप्तता के लिए बेल आउट प्लान बन कर रह गई है। गृहमंत्री पी. चिदम्बरम का यह वक्तव्य कि पाकिस्तान यदि ऐसा हमला फिर करता है, तो इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, इस बेल आउट प्लान का जीता जागता सबूत है।

केन्द्र सरकार ने 26/11 के बाद से ही पाकिस्तान के विरूद्ध एक दबाव डालने वाली डिप्लोमेसी शुरू कर रखी थी। भाजपा ने भी राष्ट्र हित में सरकार के इस कदम का समर्थन किया था, किन्तु पाकिस्तान आज तक भी इनकार पर इनकार किए जा रहा है। ऐसा लगता है कि भारत सरकार अब पाकिस्तान को भविष्य में ऐसा न करने की चेतावनी दे रही है तथा एक तरह से सरकार ने उसके वर्तमान दुष्कृत्य को माफ कर दिया है। श्री जावडेकर ने कहा कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का यह वक्तव्य स्वीकार्य नहीं है कि पाकिस्तान आतंक के संदिग्धों का इसलिए प्रत्यर्पण नहीं कर सकता है कि भारत के साथ उसकी प्रत्यर्पण संधि नहीं है। भाजपा स्मरण कराना चाहती है कि पाकिस्तान आतंक से लड़ने के संयुक्त राष्ट्र के चार्टर, विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों और सार्क चार्टर से बंधा हुआ है। पाकिस्तान कोई प्रत्यर्पण संधि न होने का बहाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है। ■

एनआईए का गठन संघीय ढांचे के विरुद्ध : भाजपा

केंद्र सरकार द्वारा आंतरिक सुरक्षा पर बुलाए गए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में एनडीए शासित राज्यों ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर कोसा। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसे संघीय ढांचे पर प्रहार बताया और कहा कि यह राज्यों को हाशिए पर लाने की चाल है।

गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन किया जाना देश की संघीय भावना के खिलाफ होने के साथ राज्यों को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई से अलग–थलग करने का प्रयास है। आंतरिक सुरक्षा पर विचार–विमर्श के लिए केंद्र की ओर से यहां आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मोदी ने कहा ''राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एएनआईए) का गठन करके केंद्र सरकार ने यह मंशा जाहिर कर दी है कि वह राज्यों को हाशिए पर डाल कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की जिम्मेदारी स्वयं लेना चाहती है।''

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था के हमारी संघीय भावना के विरुद्ध होने के बावजूद मैं कामना करता हूं कि केंद्र सरकार अपनी इस नई भूमिका में पूरी तरह सफल रहे। पोटा जैसे कानून की मांग करने में सबसे आगे रहे मोदी ने कहा कि हाल ही में संसद द्वारा गैर कानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) में किए गए संशोधन से ''यह कानून और कमजोर ही हुआ है। अगर हम आधे अधूरे मन से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का निर्णय करते हैं तो हम कभी सफल नहीं होंगे।''

उन्होंने कहा कि पोटा की तुलना में संशोधित यूएपीए में भी जमानत देने के प्रावधानों को और हल्का कर दिया गया है। इससे आतंकियों को जमानत लेने में सुविधा होगी।

गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि संशोधित कानून में पुलिस और जांच अधिकारियों की शक्तियों में भी वृद्धि नहीं की गई है। इसमें पोटा के उस प्रावधान की भी अनदेखी की गई है जिसमें निश्चित पद के पुलिस अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयान अदालत में स्वीकार्य थे।

उन्होंने आरोप लगाया कि संप्रग सरकार लंबे समय से आतंकवाद के विरुद्ध कड़े कानून की आवश्यकता की अनदेखी करती रही है जबकि ''मानवाधिकार का चैंपियन माने जाने वाले पश्चिम के कई उदारवादी लोकतंत्रों तक ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून बनाने में एक क्षण की झिझक नहीं दिखाई।''

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून–2008 और गैर कानूनी गतिविधि कानून में संशोधन को राज्य सरकारों के अधिकार में हस्तक्षेप करार दिया। उन्होंने इसे संविधान की मूल भावना के विपरीत बताया और इसमें संशोधन की मांग की। चौहान और मोदी ने मनमोहन सरकार पर आतंकवाद से लड़ने के भाजपा शासित राज्यों के कानूनों को मंजूरी नहीं देने व बांग्लादेशियों की अवैध घुसपैठ की समस्या पर चुप्पी साधे रखने की कड़ी आलोचना की है। प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ गुजरात के कानून गुजको पर अभी भी चुप्पी साधे हुए हैं, जिसे केंद्र के कहने पर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि मुंबई की घटना इसलिए संभव हुई कि हम आंतरिक सुरक्षा के मामले में एक 'साफ्ट स्टेट' के रूप में देखे जाने लगे थे। उन्होंने कहा कि देशविरोधी ताकतों ने मुंबई से काफी पहले संसद और उसके बाद पिछले वर्ष जयपुर, दिल्ली, बेंगलुरू, अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों को निशाना बनाया था। उन्होंने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देश को जागने के लिए मुंबई हमलों का इंतजार था। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में केंद्र सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी कानून 2008 के कुछ प्रावधानों को लेकर आपत्तियों को इस संघर्ष में मतभेद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

हिमाचल के मुख्यमंत्री धूमल ने केंद्र सरकार से हिमाचल को अन्तर्राज्यीय सीमाओं और निर्वासित तिब्बती सरकार को उपलब्ध करवाए जाने वाली सुरक्षा का पूरा खर्चा वहन करने और राज्य में एन.एस.जी. कमांडो की एक बटालियन स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पड़ोसी राज्यों जम्मू–कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तराखंड के साथ 1100 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है तथा राज्य का 200 किलोमीटर जनजातीय क्षेत्र चीन की सीमाओं से सटा है।

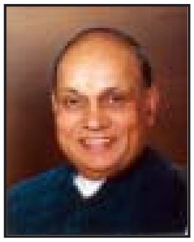

उन्होंने कहा कि राज्य पहले पंजाब तथा अब जम्मू–कश्मीर में पनपे आतंकवाद से प्रभावित रहता है और इन परिस्थितियों में सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए प्रदेश को छठी इंडियन रिजर्व बटालियन की स्वीकृति प्रदान की जाए।

मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से राज्य में रह रहे 23000 तिब्बती शरणार्थियों एवं 25000 नेपाली नागरिकों के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध भी किया। ■

भारतीय जनता पार्टी ने 2008 में लम्बी छलांग लगाई : आडवाणी

Hkkइयो और बहनो, वर्ष 2008 को बीतने में केवल दो दिन बचे हैं। वर्ष 2009 हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मैंने बताया था कि ठीक एक वर्ष पहले मैं शिमला में था। वर्ष 2007 का आखिर भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर लेकर आया था। हिमाचल प्रदेश के अलावा, हमने गुजरात में एक जबरदस्त विजय हासिल की थी।

एक वर्ष बाद, भारतीय जनता पार्टी का फिर एक अच्छी खबर के साथ अभिनन्दन हुआ है। मैं जम्मू व कश्मीर की जनता को दो बातों के लिए धन्यवाद देता हूं: पहलीः अभी–अभी सम्पन्न हुए विधानसभा चुनावों में अलगाववादी ताकतों द्वारा किए गये ''चुनाव बहिष्कार'' के आह्वान को जनता ने एकदम नकार दिया। दूसरी, भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता दिलायी।

पांच साल पहले के विधानसभाई चुनावों में हमने केवल एक सीट जीती थी लेकिन इस बार हम 11 सीटों पर विजयी हुए है। किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। एक नया गठबंधन बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी उसका हिस्सा नहीं बनेगी। लेकिन जम्मू व कश्मीर की नई सरकार का चाहे कोई भी गठन करे, मैं उनसे यह कहना चाहूंगाः

''आप अब भारतीय जनता पार्टी की और उपेक्षा नहीं कर सकते। यदि अमरनाथ प्रकरण की पुनरावृत्ति होती है तो हम चुप नहीं रहेंगे। यदि आप अलगाववादियों और आतंकवादियों से निपटने में नरम रवैया अपनाते हो तो हम चुप नहीं बैठेंगे। और यदि जम्मू व लद्दाख के न्यायसंगत हितों की अनदेखी की जाती है तो भी हम चुप नहीं रहेंगे।''

भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2008 में प्रभावी ढंग से लम्बी छलांग लगाई। भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में विजयी हुई और इसने पहली बार इस दक्षिणी राज्य में अपने बलबूते पर सरकार बनाई है।

अभी हाल ही में, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक नया जनादेश हासिल करने में सफल रही है।

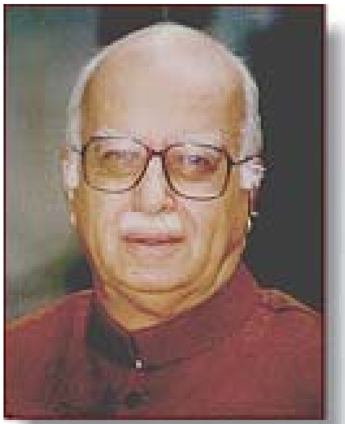

हमारा लक्ष्य : लोकसभा चुनावों में विजय हासिल करना

अब हमारा लक्ष्य हैः वर्ष 2009 में संसदीय चुनावों में विजय हासिल करना।

मै स्पष्ट रुप से देख सकता हूं कि परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि भारत की जनता नई दिल्ली में बदलाव के लिए आतुर है।

और, भारतीय जनता पार्टी ही जनता के समर्थन से इस बदलाव की अग्रदूत बनेगी।

मित्रों, कांग्रेसनीत यू.पी.ए. सरकार का पांच साल का पूरा कार्यकाल भारत के लिए एक घोर विपत्ति भरा समय रहा है। तथापि, सन् 2008 तो बहुत ही अनर्थकारी रहा है।

1. सन् 2008 में अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि हुई जिसमें आम आदमी को बहुत मुसीबतें उठानी पड़ी।
2. सन् 2008 में इस समय भयंकर आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ रहा है। लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है। हजारों व्यवसाय बंद हो गये हैं।
3. सन् 2008 में भारतीय संसद के इतिहास में राजनीतिक भ्रष्टाचार की एक बेहद शर्मनाक घटना घटी है। कांग्रेस पार्टी और इसके गठबंधन ने केवल अपनी सरकार बचाने के लिए सांसदों को बड़ी रकम देकर खरीदा।
4. सन् 2008 भारत में आतंकवादी हिंसा के मामले में सबसे बुरा साल रहा। नवम्बर के आखिरी दिनों में मुम्बई में हुए बर्बर आतंकवादी हमलों ने यह दिखा दिया कि यू.पी.ए. सरकार के शासन काल में भारत कितना कमजोर हो गया है।
5. सन् 2008 ने यह दिखा दिया कि आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए यू.पी.ए. सरकार की कोई स्पष्ट कूटनीतिक व राजनीतिक रणनीति नहीं है या कोई नीति ही नहीं है।

आतंक-विरोधी कानून पर यू.पी.ए. सरकार का ''यू. टर्न,'' लेकिन वोट बैंक राजनीति पर ''नो टर्न''

मैं आखिरी दो बिन्दुओं पर और प्रकाश डालना चाहूंगा।

मुम्बई बम विस्फोटों के बाद, यू.पी.ए. सरकार जिसने पहले पोटा को निरस्त करते हुए काफी गर्व महसूस किया था, को एक सशक्त आतंक–विरोध कानून की आवश्यकता पर यू–टर्न लेने पर विवश होना पड़ा। वर्ष 2002 में पोटा कानून बनाते समय कांग्रेस पार्टी के प्रतिकूल रवैये के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने दो महत्वपूर्ण आतंक विरोधी विधेयकों को पारित कराने में यू.पी.ए. सरकार का पूरी तरह से समर्थन किया।

यद्यपि यू.पी.ए. सरकार ने आतंक–विरोधी कानून के मुद्दे पर यू–टर्न लिया है, लेकिन जहां तक वोट बैंक राजनीति का सम्बंध है, सरकार नो–टर्न की अपनी नीति पर अड़ी हुई है।

इस सरकार ने अपने उस मंत्री को नहीं हटाया जो मुम्बई में हुए 26 नवम्बर के हमलों के दौरान एक पुलिस अधिकारी की हत्या के पीछे किसी तथाकथित षड्यंत्र के बारे में पाकिस्तान की भाषा

बोल रहे थे।

सरकार ने, 13 दिसम्बर, 2001 को संसद पर हुए आतंकवादी हमले के अपराधी अफजल गुरु को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा के फैसले को कार्यान्वित करने से मना कर दिया है।

सरकार ने भारत में बंगलादेशियों की बड़े पैमाने पर हो रही अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए एक प्रभावी कानून बनाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश को लागू करने से इंकार कर दिया है।

कांग्रेस पार्टी ने इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर नो–टर्न की नीति इसलिए अपनाई है क्योंकि इसे अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक के खोने का डर है।

ऐसा करना राष्ट्र के लिए महंगा साबित होगा। वास्तव में, यह स्वयं कांग्रेस के लिए भी महंगा साबित हेगा

मुम्बई में आतंकवादी हमले के बाद, यू.पी.ए. सरकार भारत की जनता और अतंर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों को भ्रामक संकेत दे रही है। सरकार में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग और कांग्रेस पार्टी अलग–अलग, अक्सर एक दूसरे से भिन्न जुबानों में बातें कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री से स्पष्ट रुप से यह बताने का आग्रह करता हूं कि उनकी सरकार अपने कार्यकाल के आखिरी कुछ महीनों में पाकिस्तान से किस तरह का व्यवहार करने का इरादा रखती है। भारत की जनता को यह जानने का अधिकार है।

मैं एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की सम्पूर्ण जनता को नये वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। वर्ष 2009 आपके लिए और अन्य राज्यों की जनता के लिए खुशहाली और समृद्धि लाए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सम्बंध है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हम भारत का बेहतर भविष्य बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें हमें आपके सहयोग और समर्थन की जरुरत है। ■

श्रृंखलाबद्ध धमाकों से फिर हिला असम

असम के गुवाहाटी में नव वर्ष के पहले दिन 1 जनवरी की शाम सिलसिलेवार तीन विस्फोटों में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 50 लोग जख्मी हो गए। घायलों में छह लोगों की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस ने इन धमाकों में उल्फा का हाथ होने का संदेह जताया है। धमाके केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदम्बरम की यात्रा से कुछ घंटे पहले हुए। निजी टीवी चैनलों के मुताबिक पहला धमाका दोपहर 2.20 बजे बीरूबाड़ी इलाके में हुआ। दूसरा विस्फोट शाम 5.15 बजे भूतनाथ में व तीसरा 5.30 पर भांगागढ़ इलाके में हुआ। बीरूबाड़ी में कचरे के डिब्बे में बम रखा गया था।

आतंक को पस्त करने वाले राष्ट्रीय एजेंसी जैसे सख्त कानून और आतंकियों की रणनीति को भेदने वाले मल्टी एजेंसी सेंटर (मैक) के खोल से बाहर आते ही आतंकियों ने असम में धमाका करके देश को नई चुनौती दे डाली। आतंकियों के मंसूबे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि जब सरकार घर दुरूस्त करने की तैयारी कर रही थी, तब तक वह घर उजाड़ने की तैयारी कर चुके थे। समयबद्ध साजिश की भनक किसी को न लगने देने वाले आतंकियों ने इसे तय समय पर ही अंजाम दिया। जैसे देश के गृहमंत्री पी. चिदम्बरम असम के लिए उड़े, उनके पहुंचने के पहले वहां की धरती को लहू–लुहान कर सरकार के चाक चौबंद सुरक्षा के दावे की कलई खोल दी। ■

आतंकवाद को खत्म करने के लिए बंग्लादेश का सहयोग आवश्यक : आडवाणी

गत 1 जनवरी को गुवाहाटी के तीन भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हुए श्रृंखलाबद्ध बम–विस्फोटों की कड़ी निंदा करते हुए लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि जो प्रारम्भिक समाचार मिले हैं, उनसे पता चलता कि इनमें पांच लोगों की मृत्यु हो गई तथा बहुत से लोग घायल हो गए। गुवाहाटी तथा असम के दो अन्य शहरों में एक और श्रृंखलाबद्ध विस्फोटों में 88 लोगों की मृत्यु हो जाने के बाद यह एक और आतंकवादी कारनामा हुआ है।

श्री आडवाणी ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि असम की राजधानी में केन्द्रीय गृहमंत्री श्री पी. चिदम्बरम के आने से जरा पहले ही इस तरह के विस्फोट हुए। यह बात सभी जानते हैं कि असम में आतंकवादियों की कार्रवाई उन वर्गों की करतूत है जो पड़ोसी बांग्लादेश में बैठे हैं। इसलिए आज के होने वाले ये विस्फोट एक और कारण से भी अलग महत्व रखते हैं।

उन्होंने कहा कि कल ही तो बांग्लादेश की निर्वाचित प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना वाजेद ने, जिन्होंने हाल में सम्पन्न संसदीय चुनावों में भारी विजय हासिल की है, कहा था कि उनकी सरकार किसी भी आतंकवादी ग्रुप को भारत में आतंक फैलाने के लिए बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल नहीं होने देगी।

मैं नव–निर्वाचित प्रधानमंत्री के इस स्पष्ट वक्तव्य का स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि जिन लोगों का हाल के इन विस्फोटों में हाथ है, वे ढाका में बन रही नई सरकार के नेतृत्व में भारत तथा बांग्लादेश के सम्बंधों को बेहतर बनने नहीं देना चाहते हैं।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि नव वर्ष भारत और बांग्लादेश की सरकारों के बीच आतंकवाद और उग्रवाद को इस क्षेत्र से खत्म करने के लिए सहयोग करने के नए युग की शुरूआत होगी। ■

केन्द्रीय नियामक एजेंसी का गठन करे सरकार : भाजपा

Hkk जपा ने 'सत्यम' कम्पनी के चौपट हो जाने की जांच करने एवं इसमें सेबी, एमसीए, आईटी विभाग, स्टाक एक्सचेंजो, आरओसी और चार्टर्ड एकाउण्टेसी फर्मों की भूमिका के लिए सेंट्रल रेगुलेटरी एजेंसी अर्थात् केन्द्रीय नियामक एजेंसी के गठन की मांग की है। 9 जनवरी को भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सांसद डा. मुरली मनोहर जोशी ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह मांग की।

उन्होंने कहा कि वर्षों से यह 'फ्रॉड' चला आ रहा है। ऐसा लगता है कि सभी एजेंसियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोताही बरती है, चाहे वह रेगुलेटरी, मानीटरिंग अथवा असेंसिंग एजेंसी जो भी हो, जिसके कारण लाखों छोटे निवेशकों का मेहनत से कमाया पैसा डूब गया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि इस काण्ड में फंसे अधिकारियों अथवा ऐसे अन्य व्यक्तियों के प्रति तुरंत कार्रवाई की जाए, जो अपनी जिम्मेदारी ढंग से निभाने में असफल रहे।

उन्होंने यह भी मांग कि प्रधानमंत्री को भी इस असफलता पर वक्तव्य देना चाहिए, जिनके पास इस समय वित्त पोर्टफोलियो भी है ताकि उन करोड़ों लघु निवेशकों का विश्वास बहाल हो सके। इस प्रकार के प्रकरण से छोटे निवेशकों तथा बड़े निवेशकों के बीच बहुत गहरा अविश्वास पैदा हो गया है।

अभी 7 जनवरी 2009 को सत्यम घोटाले ने पूरे भारत को हिला कर रख दिया है जिसके कारण भारत के लाखों लघु निवेशक बर्बाद हो गए हैं। भारत के कार्पोरेट जगह में यह अपनी किस्म का पहला घोटाला है। सत्यम कम्पनी के चौपट हो जाने से विश्वभर में भारतीय कम्पनियों की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ा है और इससे भारतीय कम्पनियों के भारतीय लघु निवेशकों का विश्वास हिल कर रह गया है।

भारत के कम्पनी इतिहास में इस प्रथम और सबसे बड़े घोटाले में, देश की सबसे बड़ी साफ्टवेयर कम्पनियों में चौथे नं. पर रहने वाली सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लि. के डोमोटर और चैयरमेन बी रामालिंगा राजू ने बोर्ड तथा गत अनेक वर्षों से कम्पनी के खातों में हेराफेरी करने वाले अन्य व्यक्तियों के सामने अपना गुनाह कबूल किया।

'सत्यम' के 53000 कर्मचारियों का भविष्य अंधकार में पड़ गया है। हजारों लघु निवेशकों का दस हजार करोड़ से भी अधिक की राशि डूब गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम (भारत सरकार का उद्यम) की भी करोड़ो रूपए की राशि खड्डे में भी चली गई, जो उसने सत्यम में लगाई थी। भारतीय बैंकों का सत्यम में 253 करोड़ रूपए का बकाया ऋण लगा है।

बी रामालिंगा राजू के शेयरों की कीमत 26 प्रतिशत से घटकर 8 प्रतिशत रह गई और बाद में तो 2.6 प्रतिशत तक चली गई। किन्तु नियामक एजेंसियां इस सूचना को लोगों तक पहुंचाने में असफल रही। सत्यम घोटाले से भारत में कार्पोरेट गवर्नेंस के बारे में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न ही खड़ा होकर नहीं रह गया है बल्कि इससे भी बड़ा प्रश्न यह बन गया है कि आखिर इन आडिटिंग कम्पनियों, रेटिंग एजेंसियों, सेबी, कम्पनी कार्य मंत्रालय, बैंको और वित्तीय संस्थाओं, स्वतंत्र निवेशकों तथा डिस्क्लोजर्स नार्म्स की भूमिका क्या रह जाती है? यह बात एकदम असम्भव लगती है कि आडिटर्स इतने लम्बे वर्षों तक तुलन पत्रों की इतनी बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का पता नहीं लगा सके। यह बहुत अधिक संभावना लगती है कि ये आडिटर्स इस मामले में मैनेजमेंट के साथ मिले रहे होंगे।

उन्होंने कहा कि सिक्युरिटी ट्रांसेक्शन टैक्स (एसटीटी) से संग्रहीत हजारों करोड़ रूपए की राशि और एमसीए के पास इंवेस्टर प्रोटेक्शन फंड की संग्रहीत राशि का दुरूपयोग किया गया और इसे लघु निवेशकों को शिक्षित करने और उनके संरक्षण के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। इस फंड के उपयोग की जानकारी भी लोगों को दी जानी चाहिए।

उन्होंने यूपीए सरकार को पूरी अर्थव्यवस्था की लापरवाही भरी बदइंतजामी के लिए कठघरे में खड़ा किया और कहा कि यह सरकार अर्थव्यवस्था के सभी मोर्चों पर असफल रही और उसने आम आदमी के हितों की रक्षा नहीं की। प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के निवेशक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरूण सिंह, सह संयोजक श्री अशोक गोयल, मीडिया के सह–संयोजक संजय मयूख तथा राष्ट्रीय कार्यसमिति के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। ■

कमल संदेश परिवार की ओर से

सभी सुधि पाठकों को

मकर संक्रांति, लोहड़ी व पोंगल

की हार्दिक शुभकामनाएं

भारतीय अर्थव्यवस्था की पोल खोल रहा है गिरता शेयर बाजार

& Mk- 'kjn tSu

eबई स्टाक एक्सचेंज में कार्यरत शेयर व्यापारियों ने देश की नामी गिरामी कंपनियों के शेयर के भावों की हवा निकाल कर रख दी है। जैसे उत्पादित वस्तुओं के थोड़ा पुराना हो जाने पर क्लीयरेंस सेल आयोजित किया जाता है। इसके दो कारण सामने आए हैं, पूंजी की तरलता की कमी तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा शेयरों की भारी बिकवाली। इन्हीं कारणों से रिलायन्स, टाटा इन्डस्ट्रीज, हिन्डालको, गोदरेज, सेल वोल्टास, इन्फोसिस, विप्रो, सत्यम आदि के शेयर पीक पर पहुंचे भावों से 50 से 65 प्रतिशत कम भावों पर खरीदे जा सकते हैं। इसी तरह रियलटी कंपनियों जैसे डीएलएफ, यूनीटेक, ओमेक्स, अंसल, पार्श्वनाथ आदि के शेयर 80 से 90 प्रतिशत कम भावों पर तथा इन्फ्रास्टक्चर कंपनियों जैसे लेंको, जय प्रकाश, हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन, गेमल, जीएमआर के शेयर 75 से 80 प्रतिशत कम भावों पर खरीदे जा सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर से आईसीआईसीआई, एचडीएफसी से लेकर स्टेट बैंक आफ इंण्डिया, यूनियन बैंक आदि के शेयर भी 50 से 60 प्रतिशत कम भावों पर प्राप्त किए जा सकते हैं। स्थिति यह है कि शेयर सेल में पीक पर पहुंचे भावों की तुलना में इतनी अधिक गिरावट आ जाने के पश्चात भी खरीददार आगे नहीं आ रहे हैं। शायद इन्हें डर है कि शेयर सेल की इस रेट रेस में शेयरों के भावों में और अधिक कटौती हो सकती है।

देश का शेयर सूचकांक ऊंचे में 21000 अंकों की ऊंचाई तक पहुंच कर नीचे 8700 अंकों तक पहुंचा दिया गया है। प्रबल संभावना व्यक्त की जा रही है कि निकट भविष्य में सेंसेक्स का आंकड़ा वर्ष 1993 के 7500 के स्तर को छू लेगा। शेयर के भावों को अत्यधिक ऊंचाई पर ले जाने के पश्चात उसे नीचे गिराने में विदेशी संस्थागत निवेशकों का विशेष हाथ रहा है। वे भारत आए और उन्होंने शेयरों में लगभग 1.50 लाख करोड़ का निवेश किया। उन्होंने यह धन राशि अमेरिका और यूरोप के वित्तीय संस्थानों से 3 से 3.50 प्रतिशत ब्याज दरों पर उठाई। इससे शेयरों के भाव बढ़े। बढ़े भावों पर शेयर बेचकर भारी मुनाफा कमाया। उनकी देखादेखी देश के छोटे बड़े निवेशकों ने भी शेयर बाजारों में धन कमाने के लालच में अपने धन का निवेश कर दिया, तथा आगे और भाव बढ़ने की संभावना में वे बाजार से बाजार नहीं निकल पाए। आज उन्हें अपनी मूल धन–राशि का 35 से 50 प्रतिशत ही अत्यधिक कठिनाई से प्राप्त हो रहा है। लाखों छोटे निवेशक तो पूरी तरह दिवालिया हो गए हैं। उधर अमेरिका में शनैः शनैः आई मंदी की मार के साथ–साथ सब प्राईम संकट ने वहां की कई निवेशक बैंकों को दिवालिया बना दिया। वहां से ली गई उधार धन राशि को चुकाने हेतु विदेशी निवेशक अपने शेयर बेचकर बाजार से बाहर होने लगे। अभी तक वे लगभग 60 हजार करोड़ शेयर बेच चुके हैं।

शेयर बाजार में वर्तमान और निकट भविष्य में आने वाली गिरावट यह सिद्ध करती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्तम्भ उतना मजबूत नहीं है, जितना कि सरकार द्वारा बताया जा रहा है। विदेशी निवेशकों के पलायन करते ही शेयर बाजार पूरी तरह लड़खड़ा गया है। यथार्थ में हमारे शेयर बाजार अमेरिका और यूरोप में मंदी आने के पूर्व से ही गिरना शुरू हो गया था। इसका मुख्य कारण यह है कि पिछले वर्ष से निरन्तर गतिमान महंगाई दो अंकों से कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस कमरतोड़ महंगाई ने समस्त औद्योगिक उत्पादों की मांग पर ब्रेक लगा दिया है। इसने विगत कुछ वर्षों से गतिमान 10 प्रतिशत के लगभग उत्पादन वृद्धि दर को घटाकर अगस्त 2008 में मात्र 2 प्रतिशत पर ला दिया है। स्पष्ट है हमारी अर्थव्यवस्था के डगमगाने का कारण आंतरिक ही है न कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही उथल पुथल। केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किए जाने के पूर्व से ही अमेरिका में सब–प्राईम संकट की शुरूआत हो चुकी थी। इसके निकट भविष्य में होने वाले गम्भीर परिणामों जैसे वहां की नामी बैंकों की वित्तीय स्थिति बिगड़ने की आशंका के फलस्वरूप उनसे उधार ली गई भारी धन राशि का चुकारा करने हेतु देश के शेयर बाजारों में वहां के निवेशकों द्वारा भारी बिकवाली किया जाना आदि को अवबोध (सेंस) करके इनसे निपटने हेतु बजट में नीतिगत प्रावधान करने में असफल वित्त मंत्री चिदम्बरम ने इसे चुनावी बजट का स्वरूप प्रदान कर पूर्व से जारी इन्फ्रास्टक्चर परियोजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि का 60 हजार करोड़ का किसानों के लिए ऋण राहत पैकेज 50 हजार करोड़ का सहकारिता राहज पैकेज तथा 20 हजार करोड़ का छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को अमली जामा पहुंचाने की घोषणा कर डाली। इससे केन्द्रीय सरकार का बजटरी घाटा 3.50 लाख करोड़ का दायरा पार कर गया। निरन्तर गिरते औद्योगिक उत्पादन लगातार घट रही शेयर की कीमतों के साथ साथ बढ़ती महंगाई दर तथा बेरोजगारी एवं भारी सरकारी घाटे ने हमारी अर्थव्यवसायी को भीषणतम संकट के दौर से गुजरने को मजबूर कर दिया है। इधर विश्वव्यापी आर्थिक संकट ने हमारी परेशानियां और अधिक बढ़ा दी हैं, जिसके चलते हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह असुरक्षित हो गई हैं। कदाचित यह असंभव नहीं है कि हम इस संकट से नहीं उभर सकते हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या वर्तमान सरकार के पास ऐसी प्रबल एवं दृढ़ इच्छाशक्ति बची है कि वह उसके द्वारा देश के लाखों करोड़ों छोटे–बड़े निवेशकों को जो हानि पहुंचाई गई है तथा मुद्रास्फति के बढ़ जाने से देश के उपभोक्ताओं को जो भारी वेदना हुई है इससे उन्हें बचा ले। यदि यह नहीं हो सका तो जनता को और अधिक कष्ट सहने एवं भोगने को पूरी तरह तत्पर रहना होगा। ■

(लेखक एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुख्य आर्थिक विश्लेषक रह चुके हैं।)

एक से ग्यारह हो गई भाजपा

t म्मू–कश्मीर विधानसभा चुनावों में नेशनल कांफ्रेंस भले ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी हो लेकिन सबसे ज्यादा फायदा भाजपा को हुआ है। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार दस सीटें ज्यादा मिली हैं। भाजपा की इस कामयाबी को जम्मू–कश्मीर में राष्ट्रवादी ताकतों के मजबूत होने का संकेत माना जा रहा है।

इस चुनाव में पिछली बार सत्ता में रही कांग्रेस को झटका झेलना पड़ा है। दहशतगर्दों के खौफ और अलगवावादियों द्वारा बहिष्कार के आह्वान को खारिज करते हुए इस चुनाव में 61 फीसदी से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।

tEe ,o d'ehj fo/kkulHkk pquko		
ikVh	lhV thrh	uQk@ udlku
जेकेएनसी	28	0
जेकेपीडीपी	21	+5
कांग्रेस	17	-3
भाजपा	11	+10
अन्य	10	-12

सात चरणों में हुए मतदान के नतीजे 28 दिसम्बर को आए तो सबसे चौंकाने वाला था भाजपा को 11 सीटों का मिलना। 2002 के चुनाव में भाजपा को महज एक सीट मिली थी। अमरनाथ भूमि विवाद को लेकर उठी राष्ट्रवाद की लहर भाजपा के काम आ गई। उसे 11 सीटें जम्मू रीजन में मिली हैं। इस रीजन में कुल 37 विधानसभा क्षेत्र आते हैं।

नेशनल कांफ्रेंस ने पिछला आंकड़ा बरकरार रखते हुए 28 सीटों पर जीत दर्ज की है। पांच सीटों के फायदे के साथ पीडीपी को 21 सीटें मिली हैं। तीन सीटों के घाटे के साथ कांग्रेस के खाते में आई हैं 17 सीटें। एक सीट की कमी के साथ पैंथर्स पार्टी को मिली हैं तीन सीटें। माकपा को मिली है एक सीट। छह सीटें अन्य के खातें में गई हैं। जम्मू कश्मीर भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री चमनलाल ने जम्मू में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और उप मुख्यमंत्री रहे मंगतराम शर्मा को हराया है।■

~~~~~~~~~~☯☯☯~~~~~~~~~~~

कर्नाटक : विधानसभा उपचुनाव

भाजपा को पूर्ण बहुमत

भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक विधानसभा की आठ सीटों पर हुए उप चुनाव में जबर्दस्त सफलता हासिल करते हुए पांच सीटें जीतकर सदन में पूर्ण बहुमत में आ गई है। भाजपा ने मई में विधानसभा की 224 सीटों के लिए हुए चुनाव में 110 सीटें जीती थी और छह निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई थी। भाजपा 30 दिसम्बर को घोषित आठ विधानसभा सीटों के परिणाम में पांच सीटें जीतकर अब सदन में पूर्ण बहुमत हासिल कर चुकी है। इस उपचुनाव में सत्ताधारी भाजपा के चारों मंत्रियों ने अपने–अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत लिया है। ■

भाजपा जम्मू-कश्मीर में सशक्त विपक्ष खड़ा करेगी : राजनाथ सिंह

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने जम्मू–कश्मीर विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को 'चमत्कारिक' बताते हुए कहा कि राज्य में नयी सरकार बनाने के लिए जोड़तोड़ का साथ देने के बजाए भाजपा विपक्ष में बैठेगी। श्री सिंह ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि यह चमत्कार ही है कि भाजपा विधायकों की संख्या अब 11 हो गई है जो पहले सिर्फ एक थी। जम्मू–कश्मीर के इतिहास में किसी भी पार्टी को ऐसी सफलता नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से भाजपा उत्साहित है और अब वह राज्य में एक सशक्त विपक्षी दल की भूमिका निभाएगे। उनका कहना था कि इस चुनाव में लोगों ने अमरनाथ धर्मार्थ बोर्ड की जमीन के मुद्दे पर हुए आंदोलन में भाजपा की भूमिका पर अपनी मुहर लगायी है।

श्री सिंह ने कहा कि भाजपा जम्मू–कश्मीर को विशेष दर्जा देने के भारतीय संविधान की धारा 370 को निरस्त करने की भाजपा की मांग है और अब पार्टी कश्मीर के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाएगी।■
~~~~~~~~~~

जनता ने 'गुरुजी' को सिखाया सबक
झारखंड के मुख्यमंत्री 'शिबू सोरेन' उपचुनाव हारे

झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी व झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को तमाड़ विधानसभा उपचुनाव में करारी हार का सामना पड़ा। झारखंड पार्टी के राजा पीटर ने उन्हें कड़ी शिकस्त दी। यह सिर्फ सोरेन और झारखंड सरकार की हार नहीं हैं, यह कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की भी हार है। इसके साथ ही यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की हार है। शिबू सोरेन मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उपचुनाव हारने वाले देश के तीसरे मुख्यमंत्री हैं। पहले मध्यप्रदेश से कैलाश नाथ काटजू और उत्तर प्रदेश में त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री रहते हुए उपचुनाव हारे थे।

उल्लेखनीय है कि गत 8 जनवरी को नगाड़ा छाप से चुनाव लड़ रहे झारखंड पार्टी के प्रत्याशी राजा पीटर ने शिबू को 8973 मतों से पराजित किया। पीटर को 34,127 वोट मिले, जबकि शिबू 25,154 वोट लेकर दूसरे स्थान पर रहे। आजसू प्रत्याशी विजय सिंह मानकी को 15,615 और जदयू प्रत्याशी वसुंधरा मुंडा को 9974 वोट मिले।

'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' की तर्ज पर शिबू सोरेन तमाड़ के लोगों को राजनीतिक दृष्टि से अपरिपक्व बता रहे हैं जबकि सचाई यह है कि जनता ने सोच–समझकर सोरेन को सबक सिखाया हैं। जनता ने यह संदेश दिया है कि जनाकांक्षाओं की अनदेखी कर मुख्यमंत्री थोपने की प्रवृत्ति ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। अफसोस इस बात का है कि इतनी दुर्गति के बाद भी शिबू सोरेन जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को समझने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्हें लगता है कि वह एक बार फिर सौदेबाजी कर कोई पद हासिल कर ही लेंगे। इसलिए अभी से ही वह कहने लगे हैं कि वह केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। अच्छा होता वह उपचुनाव का परिणाम आते ही तत्काल इस्तीफा दे देते। लेकिन ऐसा न करके उन्होंने अपनी रही–सही साख भी गंवा दी है। सोरेन की हार ने झारखंड में यूपीए की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचाया है। ■

सोरेन को बर्खास्त करे सरकार : भाजपा

झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के विधानसभा उपचुनाव हार जाने पर भाजपा ने उन्हें तुरंत बर्खास्त कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने और लोकसभा के साथ नए चुनाव कराए जाने की माँग की है। पार्टी प्रवक्ता श्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने अपनी 'उपयोग करो और फेंको' की चिर–परिचित नीति के तहत सोरेन को हराने में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री रहते इस शर्मनाक हार के बाद सोरेन को बिना देर किए इस्तीफा दे देना चाहिए और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो केन्द्र को उन्हें तुरंत बर्खास्त कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाकर लोकसभा चुनाव के साथ नए चुनाव कराने चाहिए।

श्री प्रसाद ने कहा कांग्रेस और राजद झारखंड में पिछले ढाई साल से काफी राजनीतिक नौटंकी खेल चुके हैं और अब उस पर विराम लगाने की जरूरत है।

उन्होंने यह दावा भी किया कि सोरेन को हरवाने में कांग्रेस और राजद की भूमिका रही है। उनके अनुसार सोरेन तमाड़ से नहीं, बल्कि संथाल क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस और राजद ने उन्हें अपने प्रभाव वाले तमाड़ से लड़ने के लिए फँसा लिया और बाद में उनकी मदद नहीं की।

यह पूछे जाने पर कि ऐसे में भाजपा क्या सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से मिल कर सरकार बनाने का प्रयास करेगी, श्री प्रसाद ने कहा हम उनके साथ किसी तरह का तालमेल नहीं चाहते। हम वहाँ सीधे चुनाव चाहते हैं। ■

गाजियाबाद (उ.प्र.)

धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे राजनाथ सिंह

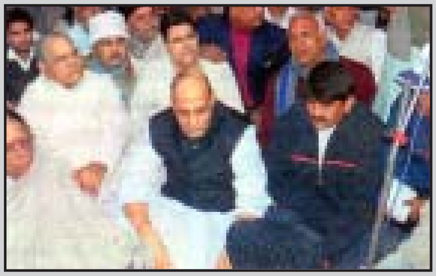

ईस्टर्न पेरिफेरियल एक्सप्रेस–वे के लिए अधिग्रहीत होने वाली जमीन का मुआवजा मार्केट रेट से तय करने की मांग को लेकर जारी आंदोलन को भाजपा ने समर्थन देने की घोषणा की है। गत 1 जनवरी को पिछले 11 दिनों से कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठे किसानों के बीच पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी मांगों के लिए वे प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। यूपी गवर्नमेंट से भी बातचीत की जाएगी। यदि फिर भी सुनवाई न हुई तो किसानों का मसला लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में गूंजेगा। उन्होंने कहा कि यदि चार माह बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो पहला तोहफा किसानों को ही मिलेगा। उनकी अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा मार्केट रेट से तय करने के लिए एक्ट में भी बदलाव किया जाएगा।

राजनाथ सिंह ने किसानों को सुझाव दिया कि वे अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग ही जारी रखे। उन्होंने मेयर दमयंती गोयल, विधायक सुनील शर्मा, महानगर अध्यक्ष अशोक मोंगा और पूर्व सांसद डॉक्टर रमेश चंद तोमर आदि का नाम लेते हुए कहा कि वे किसानों के आंदोलन में साथ रहें। ■

हम चाहते है हिमाचल विकास के शिखर तक पहुंचे- प्रो. धूमल

प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने 30 दिसम्बर को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा किया। श्री धूमलजी से 'कमलसंदेश' के लिए अम्बाचरण वशिष्ठ ने विशेष भेंट कर वार्ता की। श्री धूमल ने बातचीत करते हुए विभिन्न विषयों पर अपनी व्यापक सम्मति प्रगट की। उन्होंने एक वर्ष के अपने कार्यकाल में जहां उपलब्धियों की बात की तो साथ ही वे अपनी भावी योजनाओं प्रस्तुत करना भी नहीं भूले। अपने पिछले कार्यकाल में वे 'सड़कवाला' और 'बिजली वाला' मंत्री के नाम से विख्यात हुए थे। इस बार उनकी कामना है कि मैं हिमाचल प्रदेश के सम्पूर्ण विकास को नई ऊंचाई दूं। हम यहां उनके साथ हुए साक्षात्कार के प्रमुख अंश प्रस्तुत कर रहे हैं:–

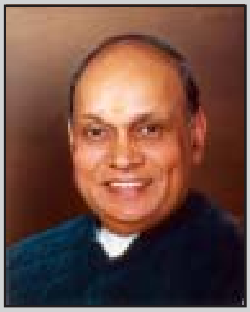

– आपने हिमाचल के मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल का प्रथम वर्ष पूरा किया है। इस अवसर पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं?

निश्चित ही यह बड़ा ही आनन्दायक अनुभव है कि मुझे फिर से लोगों की सेवा करने का अवसर मिला। मैं राज्य के लोगों के सामने श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूं जिन्होंने मुझे फिर से उनकी सेवा करने का अवसर और गौरव प्रदान किया है। इसके लिए मैं 'ईश्वर' को हार्दिक धन्यवाद देता हूं और हिमाचल के लोगों के प्रति भी अपना आभार प्रगट करता हूं जिन्होंने फिर से मेरे प्रति अपना विश्वास बनाए रखा।

– आप पिछले वर्ष में जितना कुछ कर पाए या सफलताएं प्राप्त हुई, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं?

जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं राज्य के लिए जो कुछ भी कर पाया और जितनी भी सफलताएं मिलीं, उनसे मैं अत्यधिक संतुष्ट हूं। हमने अपने चुनाव घोषणापत्र को अपने कार्यक्षेत्र का एक सरकारी नीतिगत दस्तावेज बना लिया है। पहले ही वर्ष में, हमने लोगों के साथ किए गए वायदों का लगभग 80 प्रतिशत भाग पूरा कर दिया है।

– क्या आप अपनी उपलब्धियों में से ऐसी कुछ उपलब्धियां बता सकते हैं, जिन्हें आप अत्यंत चमत्कारी समझते हों?

पहली बात तो यही है कि हमने हिमाचल के लोगों का विश्वास जीता है और वे यह महसूस करते हैं कि यह सरकार आम आदमी की सरकार है।

बातें और भी हैं, परन्तु एक बात जिसका उल्लेख करना चाहूंगा, वह है केन्द्र सरकार को सिद्धांत रूप में इस बात पर राजी कर लेना किया तो पठानकोट–जोगिन्दरनगर को नेरो–गेज रेलवे लाईन से ब्राड–ग्रेज में बदल दिया जाए और इसे कुल्लू–मनाली लेह तक आगे बढ़ा दिया जाए या फिर इस प्रस्तावित भानुपल्ली–बिलासपुर रेलवे लाईन से जोड़ दिया जाए। पहले, भारत सरकार ने मेरे प्रस्ताव को अव्यावहारिक तथा अलाभप्रद कह कर खारिज कर दिया था। परन्तु मैंने इस बात पर जोर देते हुए फिर से केन्द्र सरकार को लिखा कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो और तिब्बत के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा की हो तो वित्तीय बाधाएं और आर्थिक लाभ जैसी बातें बीच में रूकावट नहीं बननी चाहिए। मुझे खुशी है कि अन्ततः भारत सरकार मेरी बात को स्वीकार किया और अब सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस परियोजना के आने से राज्य की संचार व्यवस्था और पर्यटन में भारी क्रांति आ जाएगी।

– आपके पिछले कार्यकाल में आप 'सड़कवाला' और 'बिजली वाला' मुख्यमंत्री के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। आपके वर्तमान शासनकाल की क्या प्रमुख विशेषताएं रहेंगी?

इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि फल–उत्पादकों और आम आदमी को रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान कर उनके जीवन को समृद्ध बनाया जाए।

– आज आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

आज सबसे बड़ी चुनौती धन संग्रह की है, ताकि हम विकास कार्यों को पूरा कर सकें, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की आवश्यकताएं पूरी कर सकें और ऋण चुकता कर पाएं।

चुनौती यह भी है कि हिमाचल प्रदेश देश का प्रमुख बिजली केन्द्र बने और सम्पूर्ण विकास को आकाश के शिखर तक पहुंचा दिया जाए।

– सत्ता में लौटने के बाद और आपके द्वारा रिक्त की गई हमीरपुर लोकसभा सीट पर भारी विजय मिलने के बाद अब अगले वर्ष लोकसभा के चुनाव आपके लिए और भाजपा के लिए बड़ी भारी चुनौती होगी। इस बारे में आपकी और भाजपा की क्या रणनीति रहेगी?

हमारी रणनीति बहुत सरल है: हम सभी चारों सीटों पर विजयी रहें। इसके लिए सरकार और संगठन पहले की तरह मिलजुल कर काम करेंगे।

– वे कौन से मुद्दे रहे जिन्हें लक्ष्य बनाकर आपका चुनाव–अभियान चलेगा?

हमारा अभियान दो मुद्दों पर संकेन्द्रित रहेगाः गत एक वर्ष में वर्तमान भाजपा सरकार की उपलब्धियां तथा राज्य की पिछली कांग्रेस की विफलताएं; और केन्द्र में श्री वाजपेयी के

नेतृत्व में एनडीए सरकार ने जिस प्रकार का हिमाचल प्रदेश को अनुपम संरक्षण प्रदान किया था, उसकी तुलना में आज यूपीए सरकार राज्य को कुछ सी सहयोग प्रदान करने में एकदम विफल सिद्ध हुई है।

– आपको श्रेय जाता है कि आपने हिमाचल में पुराने एवं नए क्षेत्रों के बीच युगों पुरानी खाई को पाटने में सफलता प्राप्त की। यह खाई और कितनी भरी गई है– इस बारे में आप क्या समझते हैं?

वस्तुतः, यह कांग्रेस पार्टी ही थी, जिसने 1966 में हिमाचल में पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों के विलय के समय से ही इस अन्तर को बनाए रखा था। वे कभी भी इस दरार को अपने निहित चुनावी स्वार्थों के लिए कम करना और भरना नहीं चाहते थे। भाजपा ने पहली बार जुब्बल–कोटखाई सीट जीत कर एक इतिहास रच दिया था। हमने शिमला संसदीय सीट की 17 विधान सभा सीटों में से 8 सीटों पर विजय हासिल की थी। एक कांग्रेसी असंतुष्ट विधायक ने निर्दलीय रूप से सीट जीती थी जो बाद में भाजपा का सदस्य बन गया। मेरी सरकार इन दो क्षेत्रों के बीच सद्भाव पैदा कर इसे और भी सुदृढ़ बनाने का प्रयास करेगी।

– राजस्थान और दिल्ली के हाल के विधानसभा चुनाव–परिणामों ने भाजपा की रणनीति को झटका दिया है। आपके राज्य में लोकसभा चुनावों के विशेष संदर्भ में आप इसे किस रूप में देखते हैं?

हिमाचल के साथ हाल के चुनाव परिणामों की समरूपता केवल इतनी है कि अच्छे काम, विकास और लोगों के साथ निकट का सम्पर्क एवं लोगों की नस पर आपकी पकड़, इन सभी बातों से सदैव अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं।

– आप ऐसे मुख्यमंत्री समझे जाते हैं जिनसे आम लोग बड़ी आसानी से मिल लेते हैं। क्या आपके पास निकट भविष्य में ऐसी कोई योजना है जिससे आपकी सरकार और अधिक लोगों के नजदीक पहुंच सके?

सरकार के सचिवों को निर्देश दिया गया है कि वे राज्य का व्यापक दौरा करें और लोगों के घरों पर पहुंच कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। ज्यादातर लोगों की एक और शिकायत रहती है कि कार्यालय के फील्ड कर्मचारी गायब रहते हैं। मैंने कड़े आदेश दिए हैं कि अपने–अपने कार्यालयों में फील्ड–अधिकारी तथा कर्मचारी अवश्य उपस्थित रहें। शिकायत समाधान प्रणाली को चालू किया गया है और इसे इतना सुदृढ़ बनाया गया है कि 72 घण्टे के अन्दर–अन्दर, सरकार के खिलाफ चाहे जो भी शिकायत होगी, वह मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंच जाएगी, जहां उसकी मानीटरिंग हो सकेगी। वस्तुतः, ऐसे भी उदाहरण है, जिनमें देखा गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को सीधे मेरे पास भेजा गया है और उन पर तुरन्त कार्रवाई की गई है। लोकतंत्र में आम आदमी ही यथार्थ में मालिक होता है और इसलिए हर व्यक्ति का कर्त्तव्य बनता है, चाहे मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो और सरकारी अधिकारी हो, कि वह उसकी समस्याओं का समाधान करे।

– क्या आपके वर्तमान शासनकाल के दूसरे वर्ष में आपके मन में कोई अन्य विशेष कार्यक्रम भी हैं?

ऐसी अनेक योजनाएं है जिनसे आम आदमी को लाभ मिलने वाला है।

– जब पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार और संगठन के बीच कुछ मतभेद पैदा हो जाते हैं। हिमाचल में क्या स्थिति है?

हिमाचल में ऐसी जरा भी समस्या नहीं है। पार्टी और सरकार पूरे सदभाव से काम कर रहे हैं। हम एक–दूसरे से प्रायः विचार विमर्श करते रहते हैं।

आपके पिछले कार्यकाल में अनुशासनहीनता और मतभेद जैसी कुछ घटनाएं हो गई थीं। परन्तु इस बार लगता है कि स्थिति अलग दिखाई पड़ती है।

हां, यह सही है। इसी कारण, मैं राज्य के विकास और कल्याण पर और अधिक ध्यान दे पाता हूं। ■

बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी

श्री आडवाणी एवं श्री राजनाथ सिंह ने दी शेख हसीना को बधाई

Hkkजपा के वरिष्ठ नेता एवं लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने बांग्लादेश की निर्वाचित प्रधानमंत्री श्रीमती शेख हसीना को भाजपा, राजग तथा अपनी ओर से ढाका में अवामी लीग की भारी विजय पर 1 जनवरी 2009 को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने अपने शुभकामना पत्र में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन तथा अपनी ओर से भी मैं बांग्लादेश में हाल में सम्पन्न संसदीय चुनावों में अवामी लीग की अभूतपूर्व विजय पर आपको अपनी हार्दिक बधाई भेजता हूं। इस भारी जीत के पीछे अवामी लीग में करिश्माई नेतृत्व ही सबसे बड़ा कारण रहा है।

भारत के लोगों को बांग्लादेश में लोकतंत्र की वापसी पर गहरा हर्ष है। मीडिया में आपके द्वारा दिए गए इस स्पष्ट वक्तव्य को पढ़कर विशेष रूप से लोग आह्लादित हैं कि आपकी सरकार भारत की सीमा पर काम कर रहे किसी आतंकवादी और उग्रवादी संगठनों को बांग्लादेश के किसी भी क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देगी। मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप बांग्लादेश को प्रगति की ओर ले जाने के अपने प्रयास में सफल हों।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने भी शुभकामना संदेश प्रेषित करते हुए कहा कि ''यह सचमुच दक्षिण एशिया क्षेत्र के लिए शुभ समाचार है क्योंकि यह क्षेत्र अस्थिरता और आतंकवाद से बुरी तरह से प्रभावित है।

लोकतंत्र और शांति के प्रति आपके दृढ़ विश्वास से निश्चित ही बांग्लादेश में लोकतांत्रिक परम्पराओं को मजबूती मिलेगी।'' उन्होंने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि नई सरकार दक्षिण एशिया में आतंकवाद के प्रति संघर्ष को और भी मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि ''स्थिर और शांतिप्रिय बांग्लादेश न केवल बांग्लादेशियों के हित में है, बल्कि इससे पूरे क्षेत्र में सुसंगति एवं एकरूपता का भाव भी पैदा होगा।''

उन्होंने आगे कहा कि अवामी लीग के नेतृत्व में नौ पार्टियों के गठबंधन की विजय भारत तथा बांग्लादेश के बीच सौहार्दपूर्ण सम्बंधों के नए युग की भी शुरूआत करेगी। ■

भाजपा सरकार का एक साल

वादे किए तो निभाए भी

Oरिष्ठ भाजपा नेता व लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल की नेतृत्व क्षमता और जनता के प्रति समर्पण की भावना से कार्य करने की प्रशंसा की। श्री आडवाणी ने केन्द्र की यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील करते हुए कहा कि सरकार का रवैया आतंकवाद के प्रति अत्यंत नरम है। श्री आडवाणी ने विश्वास व्यक्त किया कि भाजपा के नेतृत्व में केन्द्र में राजग की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश उसमें पूरा योगदान करेगा।

हिमाचल से भाजपा ने लोकसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया है। चुनावी साल शुरू होने से ठीक पहले पार्टी ने आम चुनावों में विजय का संकल्प लिया। धूमल सरकार की पहली वर्षगांठ पर आयोजित विजय संकल्प रैली में भाजपा के श्री लालकृष्ण आडवाणी ने यूपीए सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। रैली में भाजपा नेता महंगाई और आतंकवाद पर कांग्रेस नीत केन्द्र सरकार पर खूब गरजे। संगठन में एकता का संदेश देने का भी पार्टी ने कोई मौका नहीं चूका। श्री आडवाणी जहां धूमल को यशस्वी मुख्यमंत्री कहकर पूरे नंबर दे गए, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद श्री शांता कुमार ने भी मुख्यमंत्री धूमल के एक वर्ष के कार्यकाल की भरपूर प्रशंसा की। हिमाचल के आला नेताओं ने लोकसभा की चारों सीटें जीतने के भरोसे के साथ आडवाणी को बतौर प्रधानमंत्री अगले साल शिमला आने का निमंत्रण भी दिया।

रैली में श्री आडवाणी ने कहा कि आतंकवाद राष्ट्र के खिलाफ युद्ध है। दुश्मन चाहे बाहर हो या अंदर देश पर हमला करने वालों के खिलाफ हम सब एक हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई हमले के बाद यूपीए सरकार देश की जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भ्रामक संकेत दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री स्पष्ट करें कि उनकी सरकार पाकिस्तान से किस तरह के व्यवहार का इरादा रखती है। वोट बैंक की राजनीति करते हुए आतंक का मुकाबला नहीं किया जा सकता। 'जय श्रीराम' तभी होगा जब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। श्री आडवाणी ने धूमल सरकार की एक साल की उपलब्धियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अवसर मिलने पर भाजपा विकास, जनकल्याण और सुरक्षा का माहौल देश में बनाएगी। विधानसभा चुनाव नतीजों से साफ हो गया है कि जम्मू क्षेत्र के लोग भाजपा को अपना प्रतिनिधि मानते हैं। उन्होंने

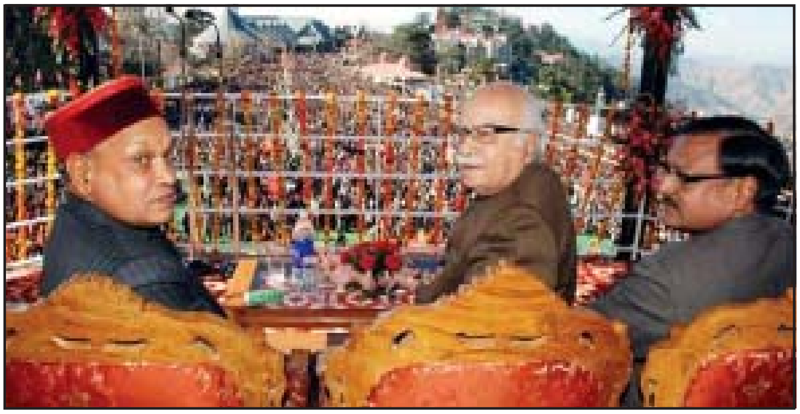

चेतावनी दी कि अलगाववादियों और आतंकवादियों के प्रति नरमी के अलावा जम्मू व लद्दाख क्षेत्रों से भेदभाव को भाजपा किसी सूरत में सहन नहीं करेगी।

महंगाई और आर्थिक मंदी ने जनता की कमर तोड़ दी है। कोई माह ऐसा नहीं जाता, जब कहीं आतंकी हमला न हो। मुंबई में आतंकी तांडव के बाद देश में दहशत का माहौल है। किसी भी राज्य या देश में सरकार ऐसी होनी चाहिए कि आतंकवादियों के मन में भय हो। भाजपा आतंकवाद के खिलाफ हर कदम का साथ देगी। यही कारण है कि पोटा को हटाने वाली यूपीए सरकार का आतंक विरोधी नए कानून पर कमियों के बावजूद एनडीए ने समर्थन किया। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के चलते अफजल गुरू को फांसी पर नहीं चढ़ाया जा रहा। बांग्लादेशियों की घुसपैठ रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

हिमाचल प्रदेश का श्री अटल बिहारी वाजपेयी से विशेष भावनात्मक सम्बंध रहा है। मैं उनसे 25 दिसम्बर को उनके जन्म दिन पर मिला था। मैं आपके साथ मिलकर उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करता हूं। उन्होंने अनुकरणीय निष्ठा और समर्पण की भावना से राष्ट्र की सेवा की है और वे प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

मुख्यमंत्री प्रो. धूमल ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उद्योग, कृषि, बागवानी और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सरकार ने चुनावों में में पूर्व किए ज्यादातर वायदे पूरे कर दिए हैं। कर्मचारी वर्ग में सबसे निचले स्तर के दैनिक वेतनभागी मजदूरों की दिहाड़ी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की गई है।

सरकार के 365 दिनों यानी मात्र 1 वर्ष में कर्मचारियों और पेंशनधारकों को 1100 करोड़ रूपए के वित्तीय लाभ दिए गए। प्रो. धूमल ने कहा कि उनकी सरकार जनता के विश्वास पर अभी तक खरी उतरी है और भविष्य में भी हम प्रदेश हित को सर्वोपरि मानकर कार्य करेंगे। ■

जनता का विश्वास हासिल करने में सफल रही भाजपा सरकार

Hkkरतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश की दो दिवसीय कार्यसमिति बैठक 27 व 28 दिसम्बर 2008 को जिला हरिद्वार के रूड़की नगर में शहीद गजेन्द्र सिंह सभागार में सम्पन्न हुई। इस बैठक में विशेष रूप से राष्ट्रीय सह महामंत्री (संगठन) श्री सौदान सिंह एवं प्रांत के सह प्रभारी श्री अनिल जैन उपस्थित थे। इस बैठक में एक राजनैतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री अजय भट्ट ने कार्यसमिति में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया।

इस प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदेश मंत्री श्री सहदेव पुण्डीर ने व समर्थन उपाध्यक्ष श्री सुरेश जोशी ने किया इस प्रस्ताव में मुम्बई में हुए आतंकवादी घटना के पश्चात घटित राजनैतिक घटनाक्रम की चर्चा करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद के कारण गत दिनों सैंकड़ों देशवासियों को जान गंवानी पड़ी थी किन्तु सम्पूर्ण राष्ट्र ने एक साथ खड़े होकर साबित कर दिया कि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि जीता जागता राष्ट्रपुरूष है। देश को 60 घंटों तक संकट में रखने वाले आतंक को कुचलने वाले वीर जवानों के सम्मान में पूरा राष्ट्र नतमस्तक है।

इस सदन के माध्यम से हम शहीद हुए जवानों व नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम उत्तराखंड के सपूत कमाण्डो गजेन्द्र सिंह बिष्ट को विशेष रूप से इसलिए नमन करना चाहते हैं कि वे भारत माता पर बाह्य एवं आंतरिक हमलों को नाकाम करने में शहादत देने की उत्तराखड की बलिदानी परम्परा के अमर सेनानी बने।

हमारे नेतृत्व ने केन्द्र सरकार को खुले तौर पर कहा कि आतंकवाद के सफाये के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम सब अपने सर्वोच्च नेतृत्व के इस आह्वान के साथ हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हर लड़ाई में भाजपा केन्द्र सरकार के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हमारे शिखर नेतृत्व श्री लालकृष्ण आडवाणी ने गीता के उदाहरण के साथ लोकसभा में वचन दिया कि ''वयं पंचाधिकम शतम्'' (अर्थात् बाहर वालों के लिए हम एक सौ पांच हैं), हम चाहते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में केन्द्र सरकार अपने सर्वश्रेष्ठ कूटनीतिक एवं राजनयिक कौशल का प्रदर्शन करे।

> ***भाजपा सरकार ने अपने नियोजन व कार्यकुशलता से प्रदेश की जनता का विश्वास अर्जित किया है। इसी विश्वास पर भाजपा ने बाजपुर, धुमाकोट विधानसभा, पौड़ी संसदीय उपचुनाव, स्थानीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत एवं सहकारिता के चुनावों में भारी सफलता प्राप्त की है।***

केन्द्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ऐसी राष्ट्रीय आपदा में भी हालातों का राजनैतिक लाभ लेना चाहते हैं। देश जानना चाहता है कि केन्द्र सरकार ने जानबूझकर उक्त बयान वोटों के लालच में तो नहीं दिलवाया, अगर ऐसा है तो यह सदन कांग्रेस नीत सरकार के इस घृणित कदम की निंदा करता है, पूर्व में कांग्रेस के सहयोगी सपा नेता अमर सिंह ने बाटला हाउस काण्ड के शहीद एवं दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्म की शहादत पर प्रश्न उठाकर संपूर्ण राष्ट्र को शर्मसार कर दिया। अटलजी के नेतृत्व वाली राजग सरकार द्वारा बनाये गए पोटा कानून को क्यों समाप्त किया गया? आतंकवाद विरोधी कोई कठोर कानून बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया? उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद भी अफजल गुरू को फांसी न देकर प्रसन्न किया जा रहा है? पूरा देश इस उदारता का कारण जानना चाहता है।

वित्त विशेषज्ञ प्रधानमंत्री व वित्तमंत्री (वर्तमान में गृहमंत्री) के समय में देश में सर्वाधिक आर्थिक मंदी के लिए यूपीए सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा गया है कि देश सर्वाधिक मंदी का दौर झेल रहा है, किन्तु केन्द्र सरकार इसे वैश्विक मंदी का बहाना बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। अगर मंदी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल, पेट्रोल के घटे हुए भाव का लाभ इस देश के नागरिक को क्यों नहीं मिल रहा है।

केन्द्र की सौतेली नीति के तहत रसोई गैस, मिट्टी का तेल, राशन व दैनिक आवश्यक वस्तुओं के प्रदेश के कांटे में कटौती कर आम जनता का हक मारा गया है, जिसकी यह सदन भर्त्सना करता है एवं शीघ्र अनुमत्य कोटे की बहाली तथा अटल जी द्वारा दिए गए औद्योगिक पैकेज को 2013 तक बढ़ाये जाने तथा केन्द्र द्वारा घोषित 15 रूपये प्रति किलो खाद्य तेल का कोटा उत्तराखण्ड को भी उपलब्ध कराने की मांग करता है।

प्रस्ताव में भाजपा नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि केन्द्र सरकार के असहयोग के बाद भी भाजपा सरकार ने अपने नियोजन व कार्यकुशलता से प्रदेश की जनता का विश्वास अर्जित किया है। इसी विश्वास पर भाजपा ने बाजपुर, धुमाकोट विधानसभा, पौड़ी संसदीय उपचुनाव, स्थानीय निकाय, त्रिस्तरीय पंचायत एवं सहकारित के चुनावों में भारी सफलता प्राप्त की है। जिला पंचायत व जिला सहकारी बैंकों के चुनावों में 80 प्रतिशत सीटें भाजपा को प्राप्त हुई वहीं सहकारिता की दोनों शीर्ष संस्थायें राज्य सरकारी बैंक व सहकारी सघ में भी भाजपा को अभूतपूर्व विजय मिली।

भाजपा सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश से 3 रू अधिक प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य तय करना, तथा न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के अतिरिक्त गन्ने से सम्बंधित

सभी देयों का भुगतान, प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक का 108 सेवा द्वारा आच्छादित होना, कुमाऊं विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का संकल्प विधानसभा में पारित करना, गढ़वाल विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के मसौदे को संसद के पटल पर रखवाने का प्रयास, मात्र पन्द्रह हजार रूपये प्रति वर्ष शुल्क द्वारा श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई का अवसर प्रदेश के आम छात्रों को उपलब्ध कराना, आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया का सरलीकरण, विधानसभा उपाध्यक्ष पद पर महिला को अवसर देकर मातृशक्ति के सम्मान के अपने संकल्प को दुहराना जैसे वे ऐतिहासिक कदम हैं जो जनता को अनुभव कराते हैं कि प्रदेश में उनकी अपनी सरकार है। पंचायतों में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाओं के चुनाव जीतने पर सरकार को बधाई यह सदन प्रेषित करता है।

पर्यटन के क्षेत्र में उत्तराखण्ड को प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रीय गैलीलियों अवार्ड–2008 बैस्ट डोमेस्टिक टूरिज्म डेस्टिनेशन प्राप्त होना, प्रथम सैफ गेम्स 2009 के लिए प्रदेश सरकार की अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आयोजन की तैयारियां, ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की उत्तर भारत में प्रथम स्थान प्राप्त होना, राज्य कर्मियों हेतु छठे वेतन आयोग की संस्तुतियां तत्काल लागू करना तथा शिक्षा मित्र, विशिष्ट बीटीसी, पीटीए, एनटीटी आदि शिक्षकों की समस्याओं के शीघ्र समाधान के सरकार के प्रयासों की यह कार्यसमिति सराहना करती है साथ ही भारत सरकार से मांग करती है कि टनकपुर–बागेश्वर, ऋषिकेश–कर्णप्रयाग एवं देहरादून–कालसी रेल लाइनों का शीघ्र सर्वे कर लाइन बिछाई जाये।

प्रतिनिधिगण, गौ सेवा आयोग गठित करने की योजना, सभी पात्र वृद्धों, विधवाओं एवं विकलांगों को पेंशन योजना का सरलीकरण, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में गूल हौज एवं पाईप लाईनों के निर्माण हेतु 1050 लाख रूपये की व्यवस्था तथा अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं को निशुल्क भोजन, वस्त्र और आवास सुविधा युक्त 16 आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन कर सरकार ने विकास से दूर रहे समाज को मुख्य धारा में लाने का प्रशंसनीय कार्य किया है। देहरादून का मास्टर प्लान जारी करने पर सरकार को सदन बधाई देता है, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराने एवं पलायन को रोकने के लिए पर्वतीय औद्योगिक पैकेज की घोषणा कर सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किया है। सैनिक बहुल उत्तराखण्ड में पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारों के कल्याण हेतु सरकार कटिबद्ध और इसी वर्ष 14 नये इसीएचएस पालीक्लीनिकों का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को प्रेषित, पहली बार हज यात्रियों को भ्रष्टाचार मुक्त, दलाल मुक्त यात्रा का लाभ व पूर्व सरकार के हज दलालों का पर्दाफाश जैसे वे ऐतिहासिक कदम हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सार्वभौमिक संकल्प का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ■

राज्य गठन के शहीदों के सपनों को साकार करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : खंडूरी

'राज्य गठन के शहीद एवं आंदोलनकारियों के सपनों को मूर्तरूप देने के लिए वर्तमान सरकार संकल्पबद्ध है और उसी के तहत विकास एवं कल्याणकारी कार्य चलाये जा रहे हैं।'

यह बात मुख्यमंत्री मेजर जनरल (से.नि.) भुवन चन्द्र खंडूरी ने नव वर्ष की शुभ बेला पर 879 लाख रूपये लागत के राजपुर रोड यू.पी.एफ.सी. कार्यालय से राजपुर–नांगल–सहस्त्रधारा रिंग रोड तक मार्ग चौड़ीकरण एवं पुनः निर्माण के कार्य का शिलान्यास करने के पश्चात कही।

मुख्यमंत्री मेजर जनरल खंडूरी ने कहा कि विकास के कार्य निरंतर चलते रहेंगे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता को आधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराने वाली योजनाओं को महत्व देते हुए समयबद्ध कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं को पूरा करें।

उन्होंने कहा कि इस मार्ग के चौड़ीकरण से राजपुर रोड पर यातायात का दबाव कम होगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा देहरादून की पुरानी सड़कों के पुनर्निर्माण एवं चौड़ीकरण कार्य कर यातायात को सुचारू करने के लिए कोशिश की गई है, किंतु शहर की आबादी एवं वाहनों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यातायात में कठिनाई आ रही है। सरकार का प्रयास है कि उपलब्ध संसाधनों एवं स्थिति के अनुसार मिलजुलकर यातायात की इस चुनौती को स्वीकार करें।

उपस्थित जन समूहों को नव वर्ष की शुभकामना देते हुए ईश्वर से कामना की कि उनके तथा उनके परिवारजनों की सुख समृद्धि के साथ प्रदेश और देश समृद्ध एवं शक्तिशाली बने और सबको ऐसी सद्बुद्धि एवं प्रेरणा दे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निष्ठा और ईमानदारी से पालन करें, ताकि प्रदेश एवं देश की उन्नति हो।

श्री खंडूरी ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के पास सड़क अवस्थापना सुविधाओं के विस्तार का कार्य काफी अधिक है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस महत्वपूर्ण विभाग द्वारा इस वर्ष में अधिक से अधिक सड़कों का निर्माण हो ताकि लोगों को यातायात की अधिक से अधिक सुविधा प्राप्त हो।

उन्होंने कहा कि वे सड़क निर्माण कार्यों का निरंतर अनुश्रवण करेंगे। विधायक राजपुर गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर है तथा उन्होंने नव वर्ष के शुभ बेला पर इस परियोजना का शुभारम्भ कर विकास के प्रति अपनी दृढ़ सोच को दिखाया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने सैनिकों के कल्याण, प्रदेश के मेधावी बच्चों को कम शुल्क में चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था, आपात चिकित्सा 108 सेवा जैसे जनहित के निर्णय कर जनता को लाभ दिलाया है। ■

'संगठन और संघर्ष' को प्रभावी बनाने का संकल्प लें : अनंत कुमार

Xत 27 दिसम्बर को भोपाल में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक का उद्घाटन करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व मध्यप्रदेश संगठन प्रभारी अनंत कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश में एक विनम्र कार्यकर्ता, जनसेवक के रूप में जो रोडमॉडल पेश किया है, उसका अनुसरण करना, मंत्रिमंडल के सहयोगियों और सभी 143 विधायकों का राजधर्म बनना चाहिए। कार्यसमिति की बैठक का शुभारंभ अनंत कुमार, थावर चंद्र गेहलोत, सुमित्रा महाजन, कैलाश जोशी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश संगठन महामंत्री माखन सिंह चौहान, बाबूलाल गौर, कृष्णमुरारी मोघे, कप्तान सिंह सोलंकी, माया सिंह, चंद्रमणि त्रिपाठी तथा अन्य प्रदेश पदाधिकारियों ने दीप प्रवलन के साथ डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी, पं.दीनदयाल उपाध्याय और पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुआ। वन्दे मातरम् का सामूहिक गायन सम्पन्न हुआ।

प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रदेश कार्यसमिति सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ है और स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने की दिशा में पार्टी कदम बढ़ा रही है। तोमर ने पिछले डेढ़–दो वर्षो से लगातार चलाए गए संगठन के अभियानों की सफलता के लिए संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार माना और कहा कि सफलता का श्रेय उन सभी को है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आने वाले अप्रैल में लोकसभा चुनाव की संभावनाओं को देखते हुए हमें इस सक्रियता को जारी रखना है। बैठक में कार्य योजना बनाई जाएगी। जिससे मिशन–2009 को सफल बनाते हुए लोकसभा चुनाव में भारी सफलता के साथ श्रीलालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में केन्द्र में एनडीए की सरकार के गठन का लक्ष्य पूर्ण करने में सभी संकल्पित प्रयासों के साथ जुटेंगे।

स्थिरता, सुशासन और विकास सफलता का मूलमंत्रः अनंत कुमार

भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक का उद्घाटन करते हुए अनंत कुमार ने कहा कि पिछले 60 वर्षों में मध्यप्रदेश में गैर कांग्रेसीजन की सरकारें कभी पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और न ही वे सत्ता में लौटीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इन दोनों मिथकों को तोड़ दिया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा सत्ता में आई हैं। इसका मूल मंत्र भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा स्थिरता, सुशासन और विकास की परिकल्पना को धरातल पर उतारना और उसकी सुखद अनुभूति जनता को कराना रहा है।

अनंत कुमार ने कहा कि पिछली बार शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने प्रदेश का नेतृत्व सौंपा था, लेकिन इस बार प्रदेश की जनता ने उन्हें सरकार बनाने का जनादेश और अवसर दिया है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और इस चुनौती पर खरे उतरने के लिए सत्ता, संगठन और कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करना होगा। मध्यप्रदेश आने वाले पांच वर्षों में देश के विकसित राज्यों, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा की पंक्ति में आगे खड़ा होगा। हम विकास के वाजपेयी मॉडल को चरितार्थ करेंगे। इसमें समन्वय बैठाने की प्रतिभा और स्वयं के अनुशासन में बंधने का संकल्प दिखाना होगा। विकास की नई परिभाषा गढ़ना होगी, जिसमें विकास तेजी से होता हुआ, जनता को अनुभव होगा। विकास संतुलित होगा और जनता के लिए होगा। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में जहां–कहीं कोई त्रुटि हुई होगी, हम उसे साहस के साथ दूर करेंगे और पूरी आक्रामकता के साथ रचनात्मक पहल करेंगे।

उन्होंने कहा कि जिस तरह विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जनादेश प्राप्त किया है, उसका लोकसभा चुनाव में हमें समर्थन प्राप्त करना होगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए तीन सूत्र बताएः कार्यकर्ता, मतदाता और मतदान के प्रति गंभीरतापूर्वक मनन और क्रियान्वयन करने का परामर्श देते हुए कहा कि हम आत्मचिंतन करते रहें। बूथ

कमेटी की बैठक, नगर, ग्राम, मंडल स्तर पर न होकर मतदान केन्द्र पर ही की जाए। मतदाता सूची का एकाधिक बार अध्ययन करें। चुनाव के पहले तीन बार मतदाताओं से संबंध स्थापित करें और मतदान केन्द्र की रणनीति गंभीरतापूर्वक बनाएं। लोकसभा चुनाव में विजय सुनिश्चित करने के लिए अनंत कुमार ने कहा कि हमें विधानसभा, जिला और लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं सम्मेलनों की रणनीति बनाकर उन्हें पूरा करने के लिए तत्काल जुट जाने की आवश्यकता है। 2004 में मध्यप्रदेश में 29 में से 25 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा विजयी हुई थी। इस बार हमें 25 से अधिक सीटें जीतने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूर्ण करना होगा। यह कार्य चुनौती भरा है, लेकिन पार्टी के कर्मठ, देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं और प्रदेश की विकासशील जनता के सहयोग से असंभव नहीं है। अनंत कुमार ने कहा कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब लालपरेड प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। लालकृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर पर ध्वजारोहण कर हमें गौरवान्वित करेंगे। उन्होंने प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आह्वान किया कि उन्हें दो मूल मंत्र ध्यान रखना है संगठन और संघर्ष, संगठन भाजपा की सत्ता को जनसेवा करने के लिए तथा संघर्ष केन्द्र सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के खिलाफ। उन्होंने कहा कि स्वर्णिम मध्यप्रदेश बनाने के लिए अब स्वर्णिम भारत के निर्माण में लोकसभा चुनाव में भाजपा को विजय दिलाने का संकल्प लेना है? बाद में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष माया सिंह ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सुधा जैन ने समर्थन किया।

मप्र के विकास के लिए बनेगी पांच साला रूपरेखा : शिवराज सिंह चौहान

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के विकास की पांच साला रूपरेखा बनाने के साथ ही विकास के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की कार्ययोजना आगामी नौ मार्च तक बनाने के निर्देश दिए हैं।

चौहान ने राज्य शासन की सात प्राथमिकताओं पर प्रभावी कार्रवाई के लिए गठित कार्य दलों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कार्य दल अपनी क्षमता और दक्षता में वृद्धि के लिए अपने क्षेत्र विशेष के विशेषज्ञों और विद्वानों को शामिल करें। इसके लिए प्रादेशिक, राष्ट्रीय और जरूरी हो तो अंतरराष्ट्रीय जानकारों की भी मदद ली जाए। बैठक में यह भी फैसला किया गया कि कृषि से जुड़े सभी विषयों पर अंतिम फैसले के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में साधिकार समिति बनाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए निर्धारित सात प्राथमिकताएं क्रम से अधोसंरचना, विकास, खेती को लाभदायी बनाना, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास, सुदृढ़ कानून व्यवस्था, भरपूर निवेश आमंत्रण में उद्योग–धंधों की स्थापना कर रोजगार के अवसरों में वृद्धि और गरीबों को सुशासन महज राजनीतिक कर्मकांड नहीं है बल्कि ये प्राथमिकताएं प्रदेश को देश का अग्रणी प्रदेश बनाने की सुविचारित कोशिशें हैं। उन्होंने कहा कि सभी कार्य दल अपनी कार्ययोजना में पर्यावरण संतुलन के बिन्दु को नजरअंदाज न करें।

चौहान ने कहा कि सभी कार्य दल अपने प्रतिवेदन को शीघ्रतिशीघ्र तैयार करें। उन्होंने कहा कि कार्य दलों की ओर से पेश प्रतिवेदन के बाद वे कार्य दलों की संयुक्त और अलग–अलग बैठकें लेंगे। ये सभी दल समय–समय पर अपने प्रतिवेदन पेश करेंगे। आगामी मार्च तक पेश होने वाले प्रतिवेदनों के आधार पर बजट की प्राथमिकताएं तय की जाएंगी। यह प्रक्रिया सतत जारी रहेगी और जरूरी होने पर नीतियों, प्रावधानों व प्रक्रियाओं में परिवर्तन लाए जाएंगे। ■

तीन साल में खत्म कर देंगे बिजली की किल्लत

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आने वाले तीन साल में गांवों को भरपूर बिजली दी जाएगी। ग्रामीण घरों और खेती के लिए अलग फीडर से बिजली मुहैया कराने के इंतजाम किए जाएंगे।

श्री चौहान ने बुधनी विकास खंड के ग्राम नारायणपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में बिजली की कमी को पूरी तरह दूर करना चाहती है। अगर प्रकृति का साथ रहा तो इस कमी को हर हाल में दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली उत्पादक योजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले बरसों में भरपूर पानी बरसेगा जिससे बिजली उत्पादन बढ़ेगा। इसके बाद पर्याप्त बिजली दी जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों को 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी। गांव और खेत के लिए अलग अलग फीडर होंगे। उन्होंने कहा कि खेतों के लिए दस से बारह घंटे तक बिजली दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि खेती घाटे का सौदा नहीं रहेगी। इसे हर हाल में फायदे का धंधा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले दो–तीन साल के दौरान किसानों के हित में कई फैसले किए और इन्हें ईमानदारी से लागू किया। नतीजे में किसानों ने काफी राहत महसूस की है। सरकार आने वाले समय में भी किसानों के साथ है और किसानों की हरसंभव मदद की जाएगी। चौहान ने कहा कि सरकार ने एक कार्य समूह बनाया है जो उन सभी संभावनाओं को खोजेगा जिससे खेती में ज्यादा से ज्यादा सुधार किया जा सके। ■

प्रधानमंत्री कुछ बताते हैं और उनके कबीना मंत्री कुछ और : राजनाथ सिंह

Hkk जपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार में बढ़ी महंगाई ने देश की जनता की कमर तोड़ने का काम किया है। इतनी महंगाई किसी भी शासन में नहीं बढ़ी।

गत 26–28 दिसंबर को सहारनपुर में आयोजित भाजपा, उत्तर प्रदेश कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते

हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने देश में बढ़ रही महंगाई पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि महंगाई को कम करने के लिए यूपीए ने आर्थिक प्रबंधन किया, लेकिन इसके बावजूद महंगाई पर काबू नहीं पाया जा सका। अब ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि यूपीए सरकार की नीतियों की वजह से महंगाई पर अंकुश लगा है, जबकि ऐसा नहीं है। वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण महंगाई कम हो रही है। भाजपा ने सत्ता में रहते कभी महंगाई नहीं बढ़ने दी। साथ ही विकास दर पर भी काबू पाये रखा।

श्री सिंह ने कहा कि बढ़ता आतंकवाद देश के लिए गंभीर चुनौती ही नहीं बल्कि चिंता का विषय भी है। यूपीए सरकार आतंकवाद के मुद्दे को हलके में लेते हुए मात्र बयानबाजी कर रही है। इस मुद्दे पर सरकार बिखरी हुई नजर आती है। प्रधानमंत्री कुछ बयानबाजी करते हैं, तो गृहमंत्री आतंकवाद के मुद्दे पर उनके विपरीत बयानबाजी करते हैं। मात्र बयानबाजी से काम चलने वाला नहीं है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए यूपीए सरकार को पाक के खिलाफ मजबूती के साथ कदम आगे बढ़ाना होगा। आतंकवाद की समाप्ति के मुद्दे पर भाजपा भी केन्द्र का पूरा–पूरा साथ देने को तैयार है। श्री सिंह ने मुस्लिमों द्वारा आतंकवादियों के खिलाफ दिये गये इस बयान की तारीफ की जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों को दो गज की जमीन भी दफनाने के लिए भारत में नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार जन्म दिन मनाने के लिए धन वसूली का कार्य कर रही है। बसपा सरकार में धन वसूली को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया गया है, जो प्रदेश की जनता के लिए घातक है। औरेया में हुई इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या ने बसपा हुकुमत को पूर्ण रूप से पर्दाफाश करने का काम किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रमापति राम त्रिपाठी ने कहा कि हम मां शाकुम्भरी देवी के पवित्र क्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। शाकुम्भरी देवी आदि शक्ति का दिव्य रूप हैं। उन्होंने कहा कि आज इस पवित्र स्थली से सभी कार्यसमिति के पदाधिकारियों को संघर्ष का बिगुल बजाना चाहिए, विजय हमारी निश्चित होगी।

इससे पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति की तीन दिवसीय बैठक का दीप प्रज्वलित कर विधिवत् रूप से शुभारंभ किया। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी अरुण जेटली, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केसरी नाथ त्रिपाठी, विधान मण्डल दल के नेता ओमप्रकाश सिंह, वरिष्ठ नेता लालजी टंडन, प्रदेश चुनाव प्रभारी कलराज मिश्र आदि को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर भाजपा के संगठन महामंत्री मांगेराम, नगर विधायक राघव लखन पाल शर्मा, जिलाध्यक्ष जसवंत सिंह, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजीव गुम्बर, श्रीमती लज्जा रानी, प्रवेश धवन, भाजपा महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष अवनीत कौर, पिंकी गुप्ता, संदीप रावत, आकाश अग्रवाल, मानवेन्द्र पुंडीर, लाज कृष्ण गांधी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव व उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अरुण जेटली ने कहा कि सपा व बसपा सरकारों द्वारा राजनीति के अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अहंकार, अराजकता व जातिवाद को बढ़ावा देने के कारण उत्तर प्रदेश संकट में है। श्री जेटली ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को यह अहसास कराया जाना चाहिए कि दूसरे देश में आतंकवाद फैलाने के लिए अपनी जमीन देने के बदले कीमत चुकानी पड़ती है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री विनय कटियार ने बैठक का समापन करते हुए कहा कि मुंबई में हमला आतंकवाद नहीं बल्कि देश के खिलाफ अघोषित युद्ध है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अड्डे नष्ट करने होंगे। इससे पहले प्रदेश के चुनाव प्रभारी श्री कलराज मिश्र ने भी कहा कि भाजपा ही पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी अड्डे समाप्त कर सकती है। ■

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी व राष्ट्रीय परिषद बैठक नागपुर में

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राष्ट्रीय परिषद की बैठक क्रमशः 6 फरवरी और 7–8 फरवरी, 2009 को नागपुर (महाराष्ट्र) में आयोजित होगी। इस बैठक की अध्यक्षता भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने सभी जिला पंचायत अध्यक्ष, संगठन मंत्री, नगरपालिका अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय परिषद सदस्य, सांसद, विधायक, प्रदेश पदाधिकारी, विधान पार्षद, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय एवं प्रदेश प्रकोष्ठ के संयोजक व सहसंयोजक, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, मेयर भी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अपेक्षित है।

इस बैठक में एक ओर जहां समसामयिक मुद्दों पर चर्चा की जायेगी वहीं हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव परिणाम एवं संगठनात्मक विषयों पर विचार–विमर्श किए जायेंगे। इसके साथ आगामी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से भी रणनीति तैयार की जायेगी। ■

असम में बहुसंख्यकों की सुरक्षा

& foeykx'k jk;

सन् 1947 से पूर्व, असम दो घाटियों में बंटा था– ब्रह्मपुत्र और सूरमा की घाटियां, जिनकी राजधानी शिलांग होती थी। 1947 में विभाजन के समय भारत में 'रायशुमारी सूरमा घाटी में की गई जिसका आधार सीमित मताधिकार पर हुआ और क्योंकि चाय बगान के श्रमिकों को वोट नहीं डालने दिया गया, इसलिए फैसला पाकिस्तान के हक में हुआ और सिल्हट जिले सहित लगभग पूरी सूरमा घाटी असम राज्य से अलग हो गई और पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगलादेश) के साथ मिल गई। अतः जब 1947 में विभाजन हुआ तो असम और सिल्हट जिले विभाजित हो गए। अब सिल्हट के केवल पांच पुलिस स्टेशन ही असम के करीमगंज जिले का भाग रह गए हैं।

साम्प्रदायिक दंगों का दौर चलते रहने के कारण बड़ी संख्या में हिन्दू विस्थापितों को असम तथा देश के अन्य भागों में शरण लेने पर विवश होना पड़ा। उस समय हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने विवश हिन्दुओं की रक्षा करने का वचन दिया था। तब पं. नेहरू ने कहा था:–

इसमें कोई शक नहीं कि जो विस्थापित लोग भारत में बसने आए हैं, उन्हें नागरिकता दी ही जानी चाहिए। यदि इस बारे में हमारा कानून अपर्याप्त रहता है तो कानून में परिवर्तन लाना होगा।''

सरदार पटेल ने राष्ट्रीय भावना को इन शब्दों में प्रतिध्वनित किया:

''हमें जो स्वतंत्रता मिली है हम उसका आनन्द तब तक नहीं उठा सकते हैं जब तक हम उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं के साथ इसे बांट न सकें। भला हम विदेशी हाथों से अपनी इस मातृभूमि को खुशी–खुशी मुक्त कराने के लिए उनके बलिदान तथा पीड़ाओं को कैसे भुला सकते हैं– जरूरी है कि आगे आने वाली घटनाओं को देखते हुए सरकार और भारत संघ के लोग उनके भावी कल्याण पर ध्यानपूर्वक और गम्भीरता से ध्यान दें।''

नेहरू– लियाकत पैक्ट 8.4.1950 को हुआ था जिसमें तत्कालीन भारत तथा पाकिस्तान की राष्ट्रीय सरकार ने अपने अपने अल्पसंख्यकों की रक्षा करने पर सहमति प्रगट की थी और साथ ही साथ 'उनके जीवन, संस्कृति और निजी सम्मान की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ली थी।' परन्तु डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आने वाले दिनों में हिन्दु अल्पसंख्यकों – विशेष रूप से पूर्वी बंगाल के इन अल्पसंख्यकों –विशेषरूप से पूर्वी बंगाल के इन अल्पसंख्यकों की बदकिस्मती को पहले से ही भांप लिया था और उन्होंने 18.4.1950 को इसके विरोध में राष्ट्रीय सरकार मंत्रिमंडल से तुरंत ही त्यागपत्र दे दिया था। अपने त्यागपत्र पर संसद में दिए अपने वक्तव्य में डा. मुखर्जी ने गहरी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा था–

''... जिन परिस्थितियों के कारण मुझे त्यागपत्र देने पर मजबूर होना पड़ा है वे है पाकिस्तान, विशेष रूप से पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों के साथ किया जा रहा व्यवहार मुझे प्रमुख रूप से चिंता दे रहा है।''

.... हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पूर्वी बंगाल के हिन्दुओं को भी, केवल मानवता के नाते ही नहीं, भारत में रक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उन्होंने पीढ़ियों से बड़ी खुशी–खुशी स्वतंत्रता की खातिर कष्ट भोगे हैं और बलिदान किए हैं और यह सब कुछ किसी प्रांतीय हितों की खातिर नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने भारत की राजनैतिक स्वतंत्रता और बौद्धिक प्रगति की नींव धरने के लिए किया था।

.... पाकिस्तानी इस्लामिक राज्य की स्थापना मजहबी है और इसका उद्देश्य हिन्दुओं तथा सिखों को सुनियोजित ढंग से बाहर निकाल देना है और उनकी सम्पत्तियों का स्वामित्व हरण करना है। यही उसकी निश्चित नीति बन गई है। इस नीति के फलस्वरूप पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का जीवन ''दुष्कर, निर्मम और व्यर्थ, बनकर रह गया है।''

> *बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद 'इंदिरा–मुजीब पैक्ट' के अन्तर्गत बनाए गए बांग्लादेश सेक्युलर संविधान भी बहुत दिन नहीं टिक सका और इसके स्थान पर 1988 में मजहबी इस्लामिक संविधान आ गया, जिसमें हिन्दुओं को फिर से बांग्लादेश का दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया।*

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी भविष्यवक्ता थे और उनकी असाधारण प्रतिभा की राजमर्मज्ञता का इसी तथ्य से पता चल जाता है जब हमने देखा है कि 1947 में पाकिस्तान की स्थापना के समय एक करोड़ चौदह लाख की हिन्दु आबादी थी अर्थात् जो कुल आबादी का 29.71 प्रतिशत बनती थी। परन्तु अब यह घटकर 9.2 प्रतिशत रह गई है। बांग्लादेश की 2001 की सरकारी जनगणना के अनुसार, बांग्लादेश (पूर्ववर्ती पूर्व पाकिस्तान) की हिन्दू जनसंख्या 61 वर्षों के बाद अभी तक भी एक करोड़ तेरह लाख की है और हिन्दू जनसंख्या का प्रतिशत 29.17 प्रतिशत से घट कर 9.2 प्रतिशत रह गया है। मात्र सामान्य दर से 2.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के अनुसार भी यह कम से कम चार करोड़ इक्तालीस लाख बढ़नी चाहिए थी।

हाल ही में ढाका विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर तथा बांग्लादेश इकानामिक्स कौंसिल के महासचिव एवं बांग्लादेश में अत्यधिक सम्मानित प्रो. अब्दुल बरखत ने ढाका की एक सेमिनार में बताया था कि बांग्लादेश में हिन्दुओं की लगभग 2,52,000 करोड़ 'टका' मूल्य की 2.2 मिलियन एकड़ की भूमि–सम्पत्ति को बांग्लादेश सरकार ने 'एनीमी प्रापर्टी एक्ट, 1965' तथा 'वेस्टेड प्रापर्टी एक्ट 1974' के अन्तर्गत जबर्दस्ती हथिया

लिया। भूमि हथियाने वालों में अवामी लीग सहित बांग्लादेश की सभी राजनैतिक पार्टियों के प्रमुख सदस्यगण थे। प्रो. बरखत ने ही यह भी बताया कि इसमें प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुरजा सेन (जिन्हें 'मास्टर दा' (1894–1934) के नाम से जाना जाता है, और जो 1930 के चिटगांव सशस्त्र हमले के हीरो थे) के पूर्वजों का घर और उनकी भूमि सम्पत्ति भी शामिल है। मास्टर दा का यह हमला देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों का सबसे बड़ा साहसी कारनामा माना जाता था जिसके लिए वे 12.12.1934 को चिटगांव जेल में सूली पर चढ़ा दिए गए थे।

बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद 'इंदिरा–मुजीब पैक्ट' के अन्तर्गत बनाए गए बांग्लादेश सेक्युलर संविधान भी बहुत दिन नहीं टिक सका और इसके स्थान पर 1988 में मजहबी इस्लामिक संविधान आ गया, जिसमें हिन्दुओं को फिर से बांग्लादेश का दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया। बांग्लादेश का संविधान'बिस्मिल्लाह–अर–रहमान–आर–रहीम से शुरू होता है और इसके अनुच्छेद 2ए में गणतंत्र राज्य के मजहब को इस्लाम घोषित किया गया है.... बांग्लादेश में जिस ढंग से हिन्दू जनसंख्या गिरती चली गई है, उसका कारण यही बताया गया है कि यहां पर निरन्तर हिन्दुओं के साथ अत्याचार, जबर्दस्ती धर्मांतरण, लूट, आगजनी, हत्याएं और हिन्दू महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं होती रहती हैं। इस प्रकार 'इस्लामिक राज्य' का मिशन, जो पूर्ववर्ती पाकिस्तान राज्य की नीति थी, अब भी उतनी ही ताकत से बांग्लादेश सरकार की वर्तमान नीति बन गई है। किन्तु यह अत्यंत दुख की बात है कि इन विवश हिन्दुओं को बांग्लादेश से निकाले जाने के बाद भी भारत में शरण नहीं मिल पाती है।

विधि सम्मत इतिहास

हमारे राष्ट्रीय नेताओं की वचनबद्धताओं के अनुसार उन उजड़ गए हिन्दू विस्थापित लोगों को असम में पुनर्वास प्रदान करने के लिए आप्रवासी (असम से निर्वासन अधिनियम 1950 (1950 का अधिनियम 10) (इसके बाद जिसे 1950 का अधिनियम कहा जाएगा) बनाया गया जो 1.3.1950 से लागू हो गया है। इसकी धारा 2 में प्रावधान है–

''2. कतिपय आप्रवासियों के निर्वासन की शक्ति यदि केन्द्र सरकार की राय है कि यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी, जो भारत के बाहर किसी अन्य स्थान का निवासी है, और वह वे इस अधिनियम के आरम्भ होने से पहले या बाद में, असम में आते हैं, और यह भी कि यदि असम में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की श्रेणी का ठहरना भारत के आम लोगों या किसी वर्ग के लोगों या असम के किसी अनुसूचित जाति के लोगों के हितों के लिए हानिकारक है तो केन्द्र सरकार आदेश दे सकती है–

(क) ऐसा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों की कोई श्रेणी भारत से या असम से ऐसे समय सीमा के अंदर और ऐसे रास्ते से, जिसका उल्लेख आदेश में किया गया है, बाहर निकल जाए; और

(ख) इस बारे में वह और भी निर्देश दे सकती है कि वह व्यक्ति या ऐसे व्यक्तियों की श्रेणी भारत या असम से बाहर निकल जाए जो भी भारत सरकार आवश्यक या जरूरी समझे।

बशर्ते कि इस धारा की कोई बात उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी ऐसे किसी क्षेत्र में किसी नागरिक अशांति या इस प्रकार की अशांति के भय के कारण, जो अब पाकिस्तान का भाग बन गया है, वहां से विस्थापित हो गया है, या ऐसे किसी क्षेत्र से अपने निवास स्थान को छोड़ गया है और जो बाद में असम का निवासी बन जाता है।''

पिछले दो दशकों से भी अधिक समय में केवल 1400 घुसपैठियों का ही पता लग पाया।

इस अधिनियम में ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनसे 'घुसपैठ' और 'नागरिक अशांति के पीड़ितों; विस्थापित व्यक्तियों के बीच का अंतर स्पष्ट हो जाता है। धारा 2 के परन्तुकों में उन लोगों को संरक्षण प्रदान किया गया है, जो नागरिक अशांति या इस प्रकार की अशांति के भय के कारण विस्थापित हो जाते हैं। असम से उत्तर–पूर्व के अन्य राज्यों के निर्माण के अनुसार, इस अधिनियम को अन्य उत्तर–पूर्वी राज्यों में भी लागू कर दिया गया है।

किन्तु, जब पाकिस्तान सरकार ने जनसांख्यिकी आक्रमण द्वारा असम पर कब्जा करने का नापाक षड्यंत्र किया और असम में बड़े पैमाने पर मुस्लिमों की घुसपैठ की तो फारेनर्स एक्ट 1946 और फारेनर्स आर्डर 1964 के अन्तर्गत गठित फारेनर्स ट्राइबुनल बहुत से मुस्लिमों को तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान वापस भेजने में प्रभावी सिद्ध हुई। इसका बहुत बड़ा कारण यह था कि फारेनर्स एक्ट/फारेनर्स आर्डर के पैरा 3 की धारा 9 में प्रमाण का भार उस आरोपित विदेशी व्यक्ति पर था कि वह सिद्ध करे कि वह 'फारेनर' नहीं है, जो अधिकांश मामलों में सिद्ध नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार उनके अवैध घुसपैठ का भण्डाफोड़ हो जाता था। उस समय एक भी हिन्दू विस्थापित व्यक्ति को वापस नहीं भेजा गया क्योंकि उस समय 1950 का एक्ट लागू था।

विदेशियों के खिलाफ अभियान के फलस्वरूप आईएमडीटी एक्ट 1983 पारित किया गया। तत्कालीन कांग्रेस–नीत राज्य सरकार ने तत्कालीन कानून राज्य मंत्री श्री अब्दुल मुहीब मजुमदार के कहने पर उक्त एक्ट का षड्यंत्र रचा। आईएमडीटी एक्ट में उन सभी विदेशियों को निष्कासित करने का प्रयास किया गया है जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के दिन 25.3.1971 के बाद भारत में आए। इस एक्ट में सभी विदेशियों को एक समान दर्जा दिया गया है, चाहे वे किसी भी धर्म से सम्बंध रखते हों और इस प्रकार कलम के एक ही झटके में 'हिन्दू विस्थापित व्यक्तियों' और 'मुस्लिम घुसपैठियों' के बीच 1950 वाले एक्ट के कारण जो अन्तर चला आ रहा था, उसे समाप्त कर दिया गया। उक्त एक्ट की धारा 4 (1) का 'ओवरराइडिंग प्रभाव' पड़ा और साथ ही साथ फारेनर्स एक्ट 1946 और इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों तथा 1950 एक्ट पर भी प्रभाव पड़ा। एक्ट की धारा 4 (2) में विशेष रूप से प्रावधान था कि 1950 एक्ट की धारा 2 के उक्त परन्तुक अवैध आप्रवासियों पर लागू नहीं होंगे अर्थात् ऐसे व्यक्ति, जो 25.3.1971 के बाद भारत में आए। इस प्रकार आईएमडीटी एक्ट ने पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के मुस्लिमों को वस्तुतः मान्यता प्रदान कर दी, जो स्वतंत्रता के बाद भी भारत में आ गए। यह बात इस तथ्य के होते हुए भी की गई कि 1947

का विभाजन साम्प्रदायिक आधार पर हुआ था और मुस्लिमों ने अपने लिए पाकिस्तान बनाना चाहा था।

आईएमडीटी का प्रारूप सरकार के घोषित उद्देश्यों के विपरीत किया गया, जिससे मुस्लिम घुसपैठियों का पता लगाना और उन्हें वापस भेजना लगभग असम्भव कार्य बन गया। इसमें फारेनर्स एक्ट 1946 से एक दम अलग हट कर प्रावधान किए गए थे क्योंकि उसमें प्रमाण का भार, जो आरोपित विदेशी व्यक्ति पर था, हटा लिया गया था और इसका मतलब यह हो गया कि अब यह भारी भार राज्य पर आ पड़ा कि वह सिद्ध करे कि आरोपित व्यक्ति 'फारेनर' नहीं है। जबकि आईएमडीटी एक्ट से पूर्व, हिन्दू विस्थापित व्यक्ति के खिलाफ कोई भी मामला ट्राइबुनल में दाखिल नहीं हुआ था और सभी मामले मुस्लिम घुसपैठियों के खिलाफ दाखिल हुए थे, जिन्हें बड़े पैमाने पर निष्कासित किया गया था। परन्तु आईएमडीटी एक्ट आने के फलस्वरूप मुस्लिम घुसपैठिए सुरक्षित हो गए। दूसरी तरफ, हिन्दू विस्थापित व्यक्तियों को 1950 एक्ट के अन्तर्गत मिली सुरक्षा खत्म हो गई और बड़ी संख्या में हिन्दुओं के खिलाफ आईएमडीटी एक्ट के अन्तर्गत मुकदमे चलाए गए। फिर भी आईएमडीटी एक्ट का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाया और पिछले दो दशकों से भी अधिक समय में केवल 1400 घुसपैठियों का ही पता लग पाया।

अन्ततः सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी एक्ट को निरस्त कर दिया और इसे असंवैधानिक घोषित किया तथा इसे असम राज्य पर लागू करने को भेदभावपूर्ण बताया। ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि आईएमडीटी एक्ट ने राज्य सरकार या आवेदक पर गलत ढंग से भारी बोझ डाला था कि वे यह सिद्ध करें कि वह व्यक्ति अवैध आप्रवासी है और उसके प्रावधान फारेनर्स एक्ट 1946 या फारेनर्स (ट्राइबुनल) आदेश 1964 के प्रावधानों की तुलना में अत्यंत कड़े थे, जो कि अवैध आप्रवासियों का पता लगाने और निर्वासित करने में कहीं कारगर थे। सुप्रीम कोर्ट ने फारेनर्स एक्ट 1946 के अन्तर्गत फारेनर्स आर्डर 1964 के अधीन गठित ट्राइबुनलों के गठन को हरी झण्डी दे दी और इससे भी अधिक महत्व की बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 1950 एक्ट पर छंटे बादलों को हटा दिया और साथ ही साथ 1950 एक्ट को असम राज्य में पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए।

उक्त ऐतिहासिक निर्णय के बाद केन्द्र सरकार की वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था में फिर से आईएमडीटी एक्ट को लाने की कोशिश की गई और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अधिव्याप्त बनाने की कोशिश हुई जिसके अन्तर्गत फारेनर्स (ट्राइबुनल फार असम) आर्डर 2006 बना कर केवल असम राज्य के लिए अधिसूचना जारी करते हुए आईएमडीटी एक्ट की असंवैधानिक प्रक्रिया को अपनाया गया। इस अधिसूचना का लेखक भी उनमें से एक था जिसने सुप्रीम कोर्ट की उक्त अधिसूचना को चुनौती दी थी और अन्ततः उक्त अधिसूचना को भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया।

> ***बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ की समस्या सामान्य रूप से देश के लिए और विशेष रूप से असम के लिए कानून एवं व्यवस्था तथा एकता व अखण्डता की दृष्टि से गम्भीर खतरा पैदा करती है।***

आईएमडीटी के असंवैधानिक घोषित हो जाने के बाद 1950 एक्ट पर छंटे बादल साफ हो गए और साथ ही साथ 1950 एक्ट के पूरे प्रावधान लागू हुए, जिससे 'विस्थापित व्यक्तियों' को सुरक्षा मिल रही थी, जो अभी तक आईएमडीटी एक्ट लागू होने से अभी तक स्थगित रखी हुई थी। फलस्वरूप यह वर्तमान स्थिति है, विस्थापित व्यक्तियों को 1950 एक्ट की सुरक्षा प्राप्त करने का हक है और उन्हें निष्कासित नहीं किया जा सकता है।

किन्तु, इन विस्थापित व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के लिए सुदृढ़ कारण हैं। यद्यपि नागरिकता अधिनियम 1955, देखिए इसकी धारा 6ए (जिसे असम समझौते के फलस्वरूप 1985 में शामिल किया गया था), में असम समझौते को व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने के विशेष प्रावधान हैं, और 25 मार्च 1971 की (कट ऑफ) तारीख को 1950 एक्ट में शामिल 'विस्थापित व्यक्तियों' की सुरक्षा के लाभ को सीमित करने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है।

हाल की घटनाएं और आगे का रास्ता

पूर्वोक्त के संदर्भ में, हाल की कानून सम्बन्धी घटनाएं और नागरिकता नियमों में किए गए संशोधन असम के लिए भी आगे के रास्ते पर रोशनी डाल रहे हैं। 2004 में एनडीए सरकार के शासन काल के अन्तिम वर्ष में नागरिकता नियमावली 1956 में संशोधन किया गया था, जिनके द्वारा गुजरात और राजस्थान राज्यों के लिए 1965 और 1971 में भारत तथा पाकिस्तान के बीच युद्धों में पाकिस्तान के जो अल्पसंख्यक हिन्दू विस्थापित हो गए थे, उनके आश्रितों को जिन्होंने भारतीय नागरिकों या भारतीय मूल के नागरिकों के साथ विवाह किया था और उन हिन्दुओं को भी जिनके पास पाकिस्तानी नागरिकता थी, जो पांच वर्ष पूर्व भारत में आ गए थे, उन्हें नागरिकता दी गई थी। प्रारम्भ में यह नियम एक वर्ष की अवधि के लिए क्रियान्वित किया गया था, परन्तु केन्द्र में वर्तमान यूपीए सरकार के सत्ता में आने के बाद इस एक वर्ष की अवधि को दो और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। इसलिए, जहां देश के राजनैतिक नेतृत्व का सम्बंध है, इसमें एकरूपता दिखाई पड़ती है कि पाकिस्तान से आए हिन्दू नागरिक– जो विस्थापित या आप्रवासी हो–उनकी सुरक्षा करना आवश्यक है और उन्हें भारतीय नागरिक के रूप में रजिस्टर किया जाए। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के शब्दों में– जो संसद में असम का विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं–

''देश के विभाजन के बाद, बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हुए और उन्हें हमारे देश में शरण लेनी पड़ी। इन अभागे लोगों को नागरिकता प्रदान करते हुए उनके प्रति हमारा रवैया अधिक उदार रहना चाहिए और यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।''

(18.12.2003 को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में दिया वक्तव्य)

फिर भी इतिहास गवाह है कि वास्तव में बांग्लादेश के विस्थापित/आप्रवासी हिन्दुओं को इस प्रकार की सुरक्षा की कहीं अधिक और तत्काल आवश्यकता है। सन् 71 की

लड़ाई के बाद बांग्लादेश का जन्म हुआ, जिसे प्रमुख रूप से देश के पूर्वी मोर्चों पर लड़ा गया था। दस्तावेज बताते हैं कि सन् 71 के युद्ध में अधिकतम मरने वाले लोग बांग्लाभाषी हिन्दू थे जो पूर्ववर्ती पूर्वी–पाकिस्तान के थे और जिन्हें उर्दू भाषी मुस्लिम पाकिस्तानी फौजों के हाथों अत्यधिक जातीय पीड़ा पहुंचाई गई थी। बांग्लादेश की जनगणना इस तथ्य की गवाह है कि सन् 71 की लड़ाई के फलस्वरूप पूर्वी मोर्चे पर हिन्दुओं पर गहरे अत्याचार हुए। 2 अगस्त 1971 के 'टाईम मैगजीन' अंक की रिपोर्ट में लिखा था:–

'' शरणार्थियों में तीन–चौथाई हिन्दू लोग थे और मरने वालों में भी अधिकांश वही थे, जिन्होंने मुस्लिम सैनिकों की नफरत के भारी अत्याचारों को सहा। अब भी पूर्वी पाकिस्तान के मुस्लिम सैनिक किसी भी व्यक्ति की लुंगी उतरवा कर देखते हैं कि उसका खतना हुआ है या नहीं, जो मुस्लिमों के लिए अनिवार्य है; यदि खतना नहीं होता है तो इसका सामान्यतः मतलब उस व्यक्ति की मृत्यु है।''

किन्तु बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर अत्याचार जारी रहे और वहां के सेक्युलर संविधान का परित्याग किया गया एवं इस्लामिक संविधान अपनाया गया तथा बांग्लादेश ने अपने पूर्ववर्ती राज्य के एक समजातीय इस्लामिक सोसाइइटी की नीतियों को अपनाना जारी रखा। बांग्लादेश में हिन्दुओं का उत्पीड़न साम्प्रदायिक तथा राजनैतिक कारणों से किया जा रहा है जिसमें विशेष रूप से रामजन्मभूमि–बाबरी मस्जिद के दुष्प्रभाव के कारण 1992 में और फिर 2001 में हिन्दुओं का नरसंहार का उल्लेख किया जा सकता है जब बांग्लादेश में खालिदा जिया सत्ता में आईं। निश्चित ही 1950 एक्ट के अर्थों में बांग्लादेश में इसे 'नागरिक अशांति' का नाम दिया जा सकता है। हिन्दुओं के जीवन और गरिमा पर किए गए इन नृशंस हमलों के कारण, जिनमें विशेष रूप से हिन्दू महिलाएं आहत हुईं, बहुत बड़ी संख्या में हिन्दुओं को मार कर असम सहित भारत में आने पर विवश कर दिया। इससे निश्चित ही हिन्दुओं का भारत में सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है क्योंकि ये नागरिक अशांति या इस प्रकार की अशांति के भय के कारण भारत आए।

बांग्लादेश में हिन्दुओं की जनसंख्या निरन्तर गिरती चली गई, जो 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद भी जारी रही और यह बात स्वयंसिद्ध है। इस बारे में हिन्दुओं और मुस्लिमों (1901–2001) के बीच बांग्लादेश की जनसंख्या का विवरण इस प्रकार है:–

tux.kuk o"k	efLye		fgUnw	
	l[;k ¼000½	izfr'kr	l[;k ¼000½	izfr'kr
1901	19113	66.1	9545	33.0
1911	21202	97.2	9952	31.5
1921	22646	68.1	10166	30.6
1931	24731	69.5	10453	29.4
1941	29509	70.3	11747	28.0
1951	32227	76.9	9239	22.0
1961	40890	80.4	9380	18.5
1974	61039	85.4	9673	13.5
1981	75487	86.7	10570	12.1
1991	93881	88.3	11179	10.5
2001		89.7		9.2

इसे देखते हुए इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेशी नागरिकों की अवैध घुसपैठ की समस्या सामान्य रूप से देश के लिए और विशेष रूप से असम के लिए कानून एवं व्यवस्था तथा एकता व अखण्डता की दृष्टि से गम्भीर खतरा पैदा करती है। परन्तु मुस्लिमों तथा हिन्दुओं के मामले में देश छोड़ कर बाहर जाने के कारण एकदम अलग प्रकार के हैं; मुस्लिमों के मामले में उनका देश से बाहर जाना बेहतर आर्थिक संभावनाएं तलाशने से लेकर असम में सुनियोजित रूप से जनसांख्यिकी आक्रमण करना रहा है तो दूसरी तरह हिन्दुओं के मामले में उन्हें अपनी जान और गरिमा बचा कर भागने पर विवश होना पड़ा है। बांग्लादेश से बड़ी मात्रा में मुस्लिमों का आप्रवासन अब असम में जनसांख्यिकी को प्रभावित करने का निश्चित खतरा बन चुका है। 2001 की पिछली जनगणना के अनुसार 1991 में मुस्लिम आबादी 28 प्रतिशत से बढ़कर 2001 में 30.92 प्रतिशत पर पहुंच गई है जबकि इसी समय में हिन्दुओं की आबादी (असमिया, बंगाली, हिन्दी भाषियों सहित) 67 प्रतिशत से घट कर 64.89 प्रतिशत हो गई है। यह प्रवृत्ति भविष्य के लिए गम्भीर भविष्यवाणी कर रही है और जब तक इस पर तुरंत हमला नहीं किया जाता है तो असम के बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यक बन जाने की स्थिति तक पहुंच जाने की गहन संभावना बन जाएगी। दरंग और उडलगिरी जिलों में हुआ हाल का रक्तरंजित इतिहास आगे आने वाले समय की गम्भीरता का सूचक है। अतः अवैध–अप्रवासियों (जिसमें हिन्दू विस्थापित व्यक्ति शामिल नहीं हैं) को देश से बाहर निकालना निश्चित ही जरूरी है और जरूरी हो जाएगा। इस अशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा अशुभ संकेत अवैध मुस्लिम आप्रवासियों द्वारा पाकिस्तान का झण्डा फहराना और 'पाकिस्तान जिन्दाबाद' के नारे लगाना है, जिससे निश्चित ही निकट भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, इस बात का पता लग जाता है)

इस लेखक का केवल एक ही मंतव्य है कि आपको इस बात से परिचित करा दिया जाए कि मानवता, कर्त्तव्य, इतिहास और कानून सभी का तकाजा है कि 'हिन्दू विस्थापित' और 'मुस्लिम अवैध–घुसपैठियों' के बीच का अन्तर स्पष्ट कर दिया जाए। दोनों के साथ एक ही मानदण्ड के आधार पर व्यवहार नहीं किया जा सकता है जैसा कि असंवैधानिक आईएमडीटी व्यवस्था के अन्तर्गत किया गया था। कानून समाप्त हो गया है और यदि कहें कि यह सदा सदा के लिए खत्म हो चुका है। इस लेखक का प्रयास यह नहीं है कि देश के वास्तविक एवं वैध मुस्लिम नागरिकों के साथ, विशेष रूप से असम के मुस्लिमों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। वे निश्चित ही हमारे समाज का हिस्सा हैं और असम तथा देश के वृहद हितों को ध्यान में रखते हुए अवैध मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान और उनका देश से निर्वासित किए जाने में उनके सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। किन्तु बांग्लादेश के हिन्दू विस्थापित व्यक्तियों को निश्चित ही भारत की अनुकम्पा और सहायता की आवश्यकता है। ■

(मूल लेख का हिन्दी अनुवाद)

मीडिया को भटकाव से बचने की आवश्यकता : राजनाथ सिंह

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने कहा कि आतंकवाद से राजनैतिक, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से लड़ने की आवश्यकता है तथा इस भूमिका को मीडिया ही बेहतर ढंग से निभा सकता है। श्री सिंह यहां जी. टी. रोड स्थित होटल वैस्ट व्यू में प्रखर पत्रकार एवं राष्ट्रवादी विचारक तेलूराम काम्बोज अभिनन्दन समिति के तत्वाधान में आयोजित समारोह को सम्बोधित कर रहे थे।

श्री सिंह ने कहा कि काम्बोज जी से उनका परिचय 17–18 वर्षों से है। उन्होंने कहा कि जब भी उन्होंने श्री काम्बोज को देखा है तो हमेशा कुछ न कुछ करते हुए ही देखा है। श्री काम्बोज राष्ट्रवादी विचारधारा के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन एक विचारधारा के प्रति समर्पित कर दिया। श्री काम्बोज हर कसौटी पर खरे उतरते हैं।

उन्होंने कहा कि आज के संदर्भों में मीडिया की भूमिका काफी बढ़ गई है। बीसवीं शताब्दी मीडिया, विज्ञान और संचार की शताब्दी रही है। उन्होंने कहा कि संचार की क्रांतियां आने के बाद मीडिया में नये युग का सूत्रपात हुआ है, परन्तु इलेक्ट्रानिक मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में ऐसी चीजें दिखाने लगता है जो परिवार के साथ बैठकर नहीं देखी जा सकती है। इन परिस्थितियों में यह समझना मुश्किल है कि हम भारत को कहां ले जाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि इस समय मीडिया में गलाकाट प्रतिस्पर्धा चल रही है, जो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्रकारिता में भटकाव आया है ऐसे में उससे बचने की आवश्यकता है। श्री सिंह ने रजानेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नेताओं की कथनी और करनी में अंतर के कारण राजनीति पर विश्वसनीयता का संकट पैदा हो गया है।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद से राजनीतिक, रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक ढंग से लड़ने की आवश्यकता है और उस भूमिका को मीडिया ही बेतहर ढंग से निभा सकता है। उन्होंने कहा कि श्री काम्बोज पत्रकारिता के मूल्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित रहे हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को अर्पित कर दिया है।

इससे पूर्व समारोह के मुख्य वक्ता एवं पांचजन्य के सम्पादक तरूण विजय ने कहा कि इस समय भारत युद्ध भूमि में खड़ा एक देश है जहां तेलूराम काम्बोज जैसे पत्रकार सैनिक के रूप में तनकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कलम सिद्ध पत्रकारिता शत्रु को परास्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह समय बहुत बड़े संघर्ष का समय है। उन्होंने कहा कि हम गौरी, गजनी और अब्दालियों के आक्रमण झेलते आये हैं, परन्तु अब जो संकट आया है उसके खिलाफ एक वीरवाणी की आवश्यकता है। हम हिन्दुत्व के प्रति कोई ऐसा कार्य न करें जिससे हमें शर्मिन्दा होना पड़े।

अभिनंदन समिति के अध्यक्ष डा. गणेशदत्त शर्मा ने कहा कि श्री काम्बोज का अभिनन्दन एक ऐतिहासिक अभिनन्दन है। उन्होंने कहा कि हम ईश्वर से कामना करते हैं श्री काम्बोज की लेखनी में अंतिम समय तक ऐसा ही दम बना रहे। जैसा अब तक बना हुआ है।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए महापौर दमयंती गोयल ने कहा कि जब कलम अपना धर्म निभाती है तो वह पराजय को भी विजय में बदल देती है। काम्बोज जी ने हमेशा सच्चे देशभक्ति की भूमिका निभाई है। कार्यक्रम का संचालन डा. वागीश दिनकर ने किया। कार्यक्रम को वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप तलवार, पूर्व सांसद डा. रमेश चंद तोमर विधायक सुनील शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार श्री बनारसी सिंह, डा. आरबीएल गोस्वामी, बलदेव राज शर्मा, पूर्व महापौर दिनेश चंद गर्ग, भाजपा निवेशक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अतुल गर्ग आदि ने भी सम्बोधित किया।

इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने अभिनन्दन ग्रंथ का लोकार्पण किया।

इस ग्रंथ का सम्पादन प्रसिद्ध लेखक शिवकुमार गोयल, कृष्ण मित्र एवं श्री अनिल असीम ने किया। अभिनन्दन ग्रंथ में अनेक संत महात्माओं, राजनेताओं, पत्रकारों एवं गणमान्य नेताओं के विचार प्रकाशित किए गए हैं। साथ ही पत्रकारिता से सम्बंधित अनेक महत्वपूर्ण लेख भी ग्रंथ में प्रकाशित किये गये हैं।

इस अवसर पर राष्ट्रीय कवि कृष्ण मित्र, वरिष्ठ पत्रकार शिवकुमार गोयल, समाज सेवी मलकीत सिंह जस्सर, पूर्व महापौर दिनेश चंद गर्ग, आलोक शर्मा, राजेन्द्र शर्मा, मुनीन्द्र आर्य, भाजपा की क्षेत्रीय अध्यक्ष लज्जारानी गर्ग, भाजपा के महानगर अध्यक्ष अशोक मोंगा, अश्वनी शर्मा, बलदेव राज शर्मा, पीएन गर्ग आदि ने भी कार्यक्रम को सम्बोधित किया। कार्यक्रम में जनपद के अनेक पत्रकार, साहित्यकार, समाजसेवी एवं राजनीतिज्ञ उपस्थित थे। ■

उत्तर प्रदेश में गुंडा और चंदा उगाही राज

Hkk जपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद श्री प्रकाश जावडेकर ने 26 दिसम्बर, 2008 को प्रेस वक्तव्य जारी कर कहा कि उत्तर प्रदेश के एक अधिकारी मनोज गुप्ता की मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर चंदे की भारी रकम न दिए जाने के कारण हुई निर्मम हत्या ने देश की जनता को गहरा आघात पहुंचाया है।

श्री जावडेकर ने कहा कि श्री गुप्ता की हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सुश्री मायावती का शासन श्री मुलायम सिंह के पूर्व के शासन से किसी भी रूप में बेहतर नहीं है। मायावती की शब्दावली में हम कह सकते हैं कि यदि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ। जाति–आधारित ये दोनों दल राजनीति के अपराधीकरण के लिए कुख्यात हैं तथा व्यवहार में अभद्रता और शासन में विफलता के प्रतीक हैं। बसपा के 8 से अधिक विधायक, जिनमें 4 मंत्री हैं, विभिन्न जघन्य अपराधों के लिए गिरफ्तार हो चुके हैं। श्री जावडेकर ने मनोज गुप्ता की निर्मम हत्या की घोर निंदा करते हुए इस हत्या–कांड की सीबीआई द्वारा जांच की जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार सीबीआई द्वारा जांच के आदेश देने में विफल रहती है तब राज्यपाल को सख्त कार्रवाई करने का सुझाव देते हुए रिपोर्ट भेज देनी चाहिए क्योंकि आम आदमी की जान और माल पर संकट के बादल छा गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में दो नारों के साथ एक आंदोलन छेड़ दिया है। नारे हैं – "गुडें चढ़े हाथी पर, गोली मार रहे हैं छाती पर" और "बसपा शर्म करो, जन्मदिन की उगाही बंद करो"।

> *भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में दो नारों के साथ एक आंदोलन छेड़ दिया है। नारे हैं – "गुंडे चढ़े हाथी पर, गोली मार रहे हैं छाती पर" और "बसपा शर्म करो, जन्मदिन की उगाही बंद करो"।*

श्री जावडेकर ने पाकिस्तान के रवैये पर चिंता प्रकट करते हुए कहा कि भारत सरकार को पाकिस्तान की राष्ट्रीय एसेंबली के उस प्रस्ताव का कड़ा विरोध करना चाहिए, जिसमें भारत पर पाकिस्तान में आतंक फैलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। आतंक की तहकीकात में भारत को सहयोग करने की बजाय पाकिस्तान ने सभ्य समाज के सभी मानकों को ताक पर रख दिया है। पाकिस्तान लगातार इंकार करता जा रहा है – यहां तक कि उसने यह मानने तक से इंकार कर दिया है कि कसाब एक पाकिस्तानी नागरिक है। इसके उलट, उसने जानबूझकर युद्धोन्माद भड़काना शुरू कर दिया है। अब, पाकिस्तान ने एक कदम आगे बढ़कर भारत पर अपनी जमीन से पाकिस्तान में आतंक फैलाने का आरोप जड़ दिया है। पाकिस्तान ने "उलटा चोर कोतवाल को डांटे" कहावत को चरितार्थ कर दिया है।

श्री जावडेकर ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि भारत के अस्तित्व को चुनौती देते हुए मुंबई में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमलों के बाद एक मास का समय बीत चुका है। दुर्भाग्यवश, भारत सरकार न तो देश के भगोड़ों को पाकिस्तान से वापस लाने में सफल हुई है और न पाकिस्तान द्वारा आतंकी कार्रवाइयों में लिप्त होने की बात ही कबूल करा सकी है। सरकार के प्रमुख मंत्रिमंडलीय सदस्य श्री अंतुले की टिप्पणी ने पाकिस्तान के भारत–विरोधी अभियान में सहायता पहुंचाई है। इंटरपोल के चीफ के उस बयान ने विश्व स्तर पर भारत के अभियान को चोट पहुंचाई है कि भारत ने अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। ■

नेपाल पशुपतिनाथ मंदिर

भारतीय पुजारियों की पुनः बहाली हो : राजनाथ सिंह

भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने 3 जनवरी को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर माओवादियों द्वारा भारतीय पुजारियों को जबरन हटाने और उनके स्थान पर अपने व्यक्तियों की नियुक्ति पर गहरी चिंता प्रगट की है।

भाजपा अध्यक्ष ने नेपाल के राष्ट्रपति श्री राम बरन यादव और प्रधानमंत्री श्री प्रचण्ड से टेलीफोन पर बातचीत की और उनसे तुरंत ही इस वर्तमान संकट का समाधान निकालने के लिए हस्तक्षेप करने को कहा। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वे इस विषय पर गौर करेंगे और आवश्यक उपाय करेंगे।

भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपतिनाथ मंदिर की महत्ता के सम्बंध में भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि "पशुपतिनाथ मंदिर एक पवित्र स्थल है जहां भारत, नेपाल तथा विश्व के अन्य देशों के हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं।

भारतीय पुजारी पिछले तीन शताब्दियों से ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मंदिर में प्रार्थना कराते आ रहे हैं और इस परम्परा के महत्व से भारत और नेपाल के सांस्कृतिक बंधन बंधे हुए हैं। वर्तमान संकट के चलते मंदिर में नियमित प्रार्थना तक में बाधा उत्पन्न हो गई है।

नेपाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि "पशुपतिनाथ मंदिर से भारतीय पुजारियों को हटाना न केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्पूर्ण उल्लंघन है, बल्कि इससे भारत के लोगों की भावनाएं भी आहत हुई हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि "भारतीय पुजारियों को हटा कर माओवादी ताकतों ने न केवल मन्दिर की शताब्दियों से चली आ रही प्राचीन परम्पराओं को आघात पहुंचाया है, बल्कि उन्होंने भारत–नेपाल के जन्मजात सांस्कृतिक बंधनों पर भी कुठाराघात करने का प्रयास किया है।" ■

डीडीए घोटाले की सीबीआई जांच हो : भाजपा

Hkk जपा नेताओं ने डीडीए के फ्लैट आवंटन घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की है। भाजपा नेताओं ने केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री अजय माकन से भी इस्तीफा मांगा है। भाजपा नेताओं ने कहा कि पूरा आवंटन रद्द कर सिर्फ दिल्लीवासियों से ही फार्म लिए जाने चाहिए। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार मल्होत्रा की अगुआई में 5 जनवरी को भाजपा विधायक दल की बैठक हुई। इसमें आमराय से डीडीए फ्लैट आवंटन घोटाले के सिलसिले में प्रस्ताव पास किए गए। भाजपा नेता मल्होत्रा ने कहा कि यह घोटाला चंद दलालों के साथ मिलकर किया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पूर्व फार्मों की जांच करवाए बिना ही दबाव में आकर डीडीए ने आनन फानन में मकानों का ड्रा निकाल दिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि डीडीए ने आवेदकों से जो अग्रिम राशि ली, उसे भी वापस नहीं किया है। भाजपा विधायक दल ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री विजय गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने अपने दामन में घोटालों की सूची में एक और घोटाला जोड़ लिया है, जो कि हाल ही में डीडीए के फ्लैट के आवंटन से साबित हो गया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण श्रेणी के आवंटन में अनियमितताएं होने के बावजूद कांग्रेस के केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री अजय माकन कहते हैं कि आवंटन रद्द किए जा सकते हैं, हमने डीडीए और दिल्ली पुलिस की आर्थिक शाखा को मामले की तह तक पहुंचने के दिशा निर्देश दिए हैं। गोयल ने कहा कि इस तरह की बातें कांग्रेस सरकारें पहले भी कई बार कहती रहीं हैं, किंतु होता कुछ भी नहीं है।

गोयल ने कहा कि सारे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों के विश्वास को तोड़ा गया है।

दिल्ली नगर निगम स्थायी समिति के अध्यक्ष बिजेंद्र गुप्ता ने डीडीए के फ्लैट के ड्रा की सीबीआई जांच करवाने की मांग की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखे पत्र में गुप्ता ने कहा कि केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री अजय माकन को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ■

गुजरात

सीमा रक्षक जवानों से मिले मोदी

X| जरात के मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि आतंकवाद के छद्म युद्ध के जरिए खूनी खेल अब भारत और ज्यादा समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा। दुश्मन सीमा पर कितने ही दुःसाहस करे, लेकिन दिन–रात पहरा दे रहे जवान इतने सक्षम और सतर्क हैं कि दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब मिल जाएगा।

श्री मोदी 3 जनवरी को उत्तर गुजरात के बनासकांठा में पाकिस्तान से सटी सीमा स्थित सुईगाम से 50 किलोमीटर दूर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की बॉर्डर आउट पोस्ट–960 के जांबाज जवानों की टुकड़ी को संबोधित कर रहे थे। नए वर्ष का पहला दिन कच्छ सीमा पर बिताने के बाद श्री मोदी ने शनिवार को बनासकांठा–पाटण की सीमा सुरक्षा के प्रबंधों के लिए दौरा किया। इस अवसर पर बीएसएफ के प्रभारी उप महानिरीक्षक आर.पी.एस. मलिक और बटालियन कमांडेंट पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़ ने श्री मोदी को सीमा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। मोदी ने सीमा पर पाकिस्तान के नगरपारकर सहित सीमावर्ती क्षेत्रों की अंतरराष्ट्रीय सीमा में वायर फेंसिंग प्रोजेक्ट का जायजा किया। मुख्यमंत्री अंतिम बॉर्डर–पीलर तक केमल–पेट्रोलिंग कर पहुंचे। खारापाट के वीरान प्रदेश में अत्यंत कठिन परिस्थितियों में शौर्य व जोश से भरे जवानों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से

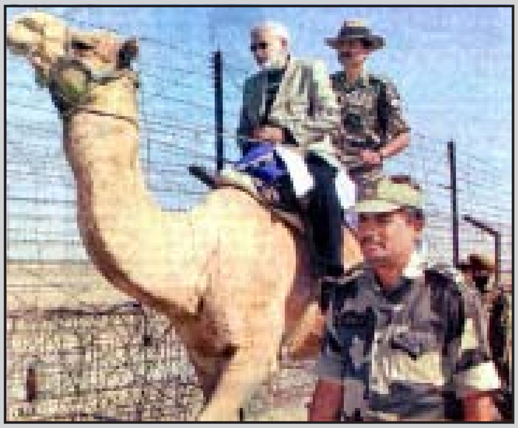

मुख्यमंत्री का स्वागत किया और समूह चित्र खिंचवाया।

श्री मोदी ने कहा कि उत्तर गुजरात व कच्छ की अंतरराष्ट्रीय सीमा की संवेदनशीलता को देखते हुए डीसा में हवाई पट्टी बनाने को शीर्ष प्राथमिकता देना चाहिए। इस संबंध में केंद्र के साथ बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि जोधपुर से नलिया की पश्चिमी सीमा पर डीसा रणनीतिक इलाका है। ऐसे में केंद्र सरकार ने डीसा की बजाए बाड़मेर हवाई पट्टी पर एकमत हैं। केंद्र को पुनर्विचार करना चाहिए।

उन्होंने नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए जवानों का मुंह मीठा कराया। इस अवसर पर मोदी ने घोषणा की कि सीमा क्षेत्र के अफाट खारे तट में जवानों के लिए छह करोड़ की लागत से नर्मदा आधारित पाइप लाइन से पानी पहुंचाने का प्रबंध सरकार ने किया। मार्च तक यह काम पूरा हो जाएगा। ■